www.ghoonghatkibagawat.com ghoonghatkibagawat37@gmail.com ghoonghatkibagawat.com

UP/HIN/1999/1282

घूँघट की बगावत

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित हिन्दी (साप्ताहिक समाचार पत्र)

वर्ष : 23 | अंक : 39 | गोरखपुर | 7 अप्रैल 2024 | पृष्ठ : 08 | मूल्य: 2/-

जल संकट पर सिद्धरामैया सरकार की वित्तमंत्री ने की समीक्षा

- सूखा राहत निधि में देरी पर की चर्चा
- जल संकट को बताया दुर्भाग्यपूर्ण

बेंगलुरू। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बेंगलुरू में जल संकट को लेकर राज्य की सिद्धरामैया सरकार को निशाना बनाते आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने पिछले साल कर्नाटक में सत्तारूढ़ होने के बाद अनेक सिंचाई तथा जल संबंधी परियोनजाओं एवं पहलों पर रोक लगा दिया। उन्होंने कथिततौर पर राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए भी कांग्रेस की आलोचना की। एक पत्रकारवार्ता के दौरान केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि यह बेहद चिंताजनक एवं दु: खद है कि शहर जल संबंधी समस्याओं से जूझ रहा है। केवल पानी उपलब्ध न होना ही एक समस्या नहीं है। शहर में हैजा फैलने को लेकर आ रही खबरें भी बहुत चिंताजनक हैं लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है कि लोगों के पास पर्याप्त पानी नहीं है। दूषित जल लोगों तक पहुंच रहा है। इसके परिणामस्वरूप पानी से जुड़ी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसा एक्ट के प्रावधानों को समझने में भूल की: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने यू.पी. मदरसा शिक्षा बोर्ड एक्ट पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को पलटते हुए कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मदरसा एक्ट को समझने में भूल की है। उच्च न्यायालय का ये मानना है कि यह एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्तों के खिलाफ है, गलत है। साथ ही शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केन्द्र, उत्तर प्रदेश सरकार और यू.पी. मदरसा एजूकेशन बोर्ड को नोटिस जारी किया है।

प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्रवार को उपरोक्त याचिकाओं पर सुनवाई की। पीठ ने यू.पी. और केन्द्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि 31 मई तक दोनों अपना जवाब दाखिल करें। मामले की सुनवाई जुलाई माह के दूसरे सप्ताह में होगी। सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय प्रथम दृष्टया सही नहीं है। ये कहना सही नहीं है कि-यह कानून धर्म निरपेक्षता का उल्लंघन है। उ.प्र. सरकार ने भी इस अधिनियम का उच्च न्यायालय में बचाव किया था। उच्च न्यायालय ने इसे गत 22 मार्च को असंवैधानिक करार दिया था, जिसके बाद से राज्य में 16 हजार मदरसों की वैधानिकता पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। यू.पी. मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम-2004 में बनाया गया था जिससे कि उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जा सके। इस-एक्ट पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय से फिलहाल उत्तर प्रदेश के 16 हजार मदरसों के 17 लाख छात्रों को बड़ी राहत मिली है।

कश्मीर में शांति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध: सेना

जम्मू। देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरो शोर से चल रही हैं। पांच सीटों के लिए चुनाव होने वाले हैं लेकिन इससे पहले पाक की नापाक हरकतें दिखाई दे रही हैं। आतंकियों के पनाहगार पाक चुनाव से पहले घाटी में आतंक फैलाकर माहौल को गंदा करना चाहता है। यह अलग बात है कि सेना के जवानों ने अपने मजबूत इरादों से इसे विफल कर दिया। ज्ञानवध क सूत्रानुसार, जम्मू और कश्मीर के बारामूला में गत दिनों (शुक्रवार) को पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिश देश में आम-चुनाव से पहले कश्मीर घाटी में अशांति फैलाने की पाकिस्तान की हताशा को प्रदर्शित करता है। बताते चला जाए कि बारामूला के पास दो आतंकी उरी सेक्टर में मारे गए। जब वे कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। सेना के अनुसार, उरी सेक्टर में एलओसी के पास घुसपैठ की योजना तैयार करने और अंजाम तक पहुंचाने वाले आतंकी समूहों के बारे में अनेक खुफिया एजेंसियों से जानकारियां प्राप्त हुईं जिन पर गंभीरता से विचार करते हुए निगरानी के आधार पर घुसपैठ रोधी ग्रिड की समीक्षा करते हुए उसे मजबूत किया गया।

सिंघवी ने दायर की याचिका

- ड्रॉ ऑफ लॉट्स पर उठाए सवाल

शिमला। हिमांचल प्रदेश से राज्यसभा चुनाव हारने के 40 दिनों के बाद कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने शनिवार की याचिका दायर की जिसके जरिये उन्होने ड्रॉ के जरिये विजेता घोषित करने के चुनाव अधिकारी के निर्णय को चुनौती दी है। सूच्य है कि गत 27 फरवरी को हुए चुनाव में भाजपा उम्मीदवार हर्ष महाजन को ड्रॉ ऑफ लॉट्स के नियम के चलते विजेता घोषित कर दिया गया था। हर्ष और सिंघवी को 34-34 मत प्राप्त हुए थे। सिंघवी ने हिमांचल प्रदेश में दायर अपनी चायिका में स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई कानून, नियम, नहीं कहता है जिस व्यक्ति का नाम लॉअरी में निकला हो और वह हार जाए। उन्होंने ड्रॉ ऑफ लॉट्स प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप पुरानी परंपरा को उठाकर देख लें। जब भी दो लोगों के बीच मुकाबला हो और लॉटरी से नाम निकालेंगे तो जिसका नाम बाहर आए उसे विजेता होना चाहिए।

सीएए किसी के लिए आमंत्रण नहीं: धनखड़

नई दिल्ली। समानता पर भारत को किसी से उपदेश लेने की जरूरत नहीं है और नागरिक संशोधन अधिनियम (सीएए) पड़ोस देशों में धार्मिक रूप से पीड़ित अल्पसंख्यकों को राहत देने के लिए है। यह विचार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने व्यक्त किया। श्री धनखड़ शुक्रवार को उत्तराखंड के मसूरी में लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में वर्ष 2023 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षु ऑफिसर्स को अपने संबोधन में विभिन्न देशों से अपने भीतर झांकने का आह्वान करते हुए कहा कि कुछ देशों में अभीतक महिला राष्ट्रपति नहीं है जबकि भारत में ब्रिटेन से भी पहले महिला प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। अन्य देशों में सुप्रीम कोर्ट ने बिना महिला न्यायाधीश के 200 वर्ष पूरे किए। लेकिन भारत में बहुत पहले महिला न्यायाधीश हो चुकी हैं।

सीएए पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि सीएए न तो किसी भी भारतीय नागरिक को उसकी नागरिकता से वंचित करता है, न ही यह पहले की तरक किसी को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से रोकता है। सीएए पड़ोसी देशों में धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की सुविधा प्रदान करता है। उन्होने कहा कि सीएए उन लोगों पर लागू होता है जा 31 दिसम्बर 2014 को या उससे पहले भारत में आए थे।

कांग्रेस ने न्यायपत्र नाम से जारी किया चुनावी घोषणा पत्र

नई दिल्ली। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया जिसमें पांच न्याय और पचीस गारंटी की बातें कही गई हैं। कांग्रेस ने इसे न्याय पत्र का नाम दिया है। पार्टी अधयक्ष मलि. लकार्जुन खरगे ने गत शुक्रवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी और राहुल गांधी की उपस्थिति में किया। कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में वायता किया कि सत्ता में आने पर जाति-जनगणना कराई जाएगी और आरक्षण की अधिकतम सीमा को 50 प्रतिशत से अधिक किया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण व सभी वर्गों के गरीबों के लिए बिना भेदभाव के लागू करेगी।

नई शिक्षानीति में राज्यों के साथ विचार विमर्श करके संशोधन किया जाएगा। पिछले दस वर्षों से हुए भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कराई जाएगी। ऊपरी अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय के साथ विचार विमर्श करके राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन किया जाएगा।

घोषणा पत्र में तीस लाख लोगों (युवाओं) को सरकारी नौकरी देने और युवाओं को एक वर्ष के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत एक लाख रूपए देने का भी वायदा किया गया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पांच न्याय (किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय और युवा न्याय) का वादा किया है। नारी न्याय में महालक्ष्मी गारन्टी दी गई है। इसके तहत गरीब परिवार की महिलाओं को एक-एक लाख रूपए प्रतिवर्ष देने, केन्द्र सरकार की नौकरियों में 50 प्रतिशत महिला आरक्षण, आशा, मिड-डे-मील, और आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को अधिक वेतन, दो गुने सरकारी योगदान, महिलाओं को कानूनी हक और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने वाली एक अधिकार सहेली हर पंचायत में कामकाजी महिलाओं के लिए दोगुने होस्टल (छात्रावास) देने का वादा किया है।

श्रमिक न्याय के तहत घोषणा पत्र में मजदूरों को स्वास्थ्य अधिकार देने, दुर्घटना बीमा, मुख्य सरकारी कार्यों में ठेकेदारी प्रथा बंद करने और शहरी रोजगार गारंटी तथा किसान न्याय के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने, कर्जम. ाफी आयोग के गठन तथा खेती को पूरी तरह जीएसटी मुक्त करने की बातें भी की गई हैं।

पापी पेट का सवाल

ककहरा सीखने की उम्र में जीवन की वास्तविकता से रू-ब-रू हो बच्ची चिलचिलाती धूप में पारिवारिक भरण-पोषण के लिए सड़क के किनारे करतब दिखाने की मजबूरी, संवेदनशील मन को झकझोर देती है।

निर्णायक साबित होंगे युवा मतदाता

लखनऊ। सियासत में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर भले ही एक मत न हों लेकिन राजधानी की मोहनलालगंज की सीट ने महिला प्रत्याशियों को हमेशा प्राथमिकता दी। राज्य की राजधानी से लगी इस संसदीय सीट पर कुल मिलाकर 42 वर्षों तक महिला का कब्जा रहा। बीते लोकसभा चुनाव में नौ बार महिलाओं ने अपनी सफलता के झंडे गाड़े। यहां से गंगोत्री (4), रीना चौधरी (2), कैलाशपति, पूर्णिमा वर्मा तथा सुशीला सरोज ने एक-एक बार जीत दर्ज की। आजादी के बाद 1952 में हुए पहले लोकसभ चुनाव में मोहनलाल संसदीय सीट से पहले सांसद कांग्रेस के रामानंद शास्त्री हुए। इसके बाद 1957, 1962, 1967 और 1971 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी की गंगा देवी ने जीत दर्ज किया। 1977 में लोकदल के पुरुष उम्मीदवार राम लाल कुरील ने यह सीट हथिया लिया। 1980 में फिर महिला प्रत्याशी कैलाश पति ने जीत दर्ज किया। 1984 में यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार जगन्नाथ प्रसाद जीते थे (लेकिन इसके बाद कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं जीत सका। 1989 में जनता दल के सूरज प्रसाद सरोज सांसद चुने गए थे। 1991 में भाजपा के छोटेलाल धोबी, 1996 में भाजपा की महिला प्रत्याशी पूर्णिमा वर्मा, ने जीत दर्ज की। 1998 में सपा के टिकट पर रीना चौधरी ने चुनाव जीता। एक वर्षोपरान्त पुन: 1999 में हुए लोकसभा चुनाव में पुन: यह सीट रीना की झोली में गई। 2004 में सपा के जयप्रकाश रावत सांसद बने। 2009 में सपा की सुशीला सरोज सांसद चुनी गईं। इस प्रकार से कुल 9 बार महिलाएं मलिहाबद से सांसद बनीं। वर्ष 2014 के चुनाव में भाजपा के कौशल किशोर तथा 2019 में कौशल किशोर ने अपनी जीत को बनाए रखा।

मतदाताओं का मानना है कि-इंडिया गठबंधन के चलते भाजपा के प्रत्याशी को चुनावी वैतरणी पार करना होगा।

जल संरक्षण के लिए सामुदायिक आन्दोलन की आवश्यकता

ज्ञानवर्धक सूत्रानुसार, इस समय दुनिया में बढ़ता जल संकट वैश्विक स्तरपर तनाव अस्थिरता में वृद्धि कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व जल दिवस के मौके पर जारी एक रिपोर्ट में यह चेतावनी दी है। यूएन की जारी रिपोर्ट यूएन वल्ड वॉटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 की थीम 'शांति और समृद्धि के लिए जल जंरूरी' रखी गयी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी के लिए स्वच्छ जल की उपलब्धता दुनिया में शांति के लिए जरूरी है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया में फिल. हाल करीब एक-चौथाई मानवता यानी 2.2 अरब लोगों की पहुंच स्वच्छ पेयजल तक नहीं है और 3.5 अरब लोग स्वच्छ और साफ स्थितियों में जीवनयापन नहीं कर रहे हैं रिपो. र्टमें यह भी कहा गया है कि जल संकट का पहला शिकार बालिकाएं और महिलाएं होती हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली, क्योंकि परिवार के लिए पानी लाने और संग्रह करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से उन्हीं पर होती है। रिपोर्ट के अनुसार लड़कियों को अस्वच्छ हालात में दिन के कई घंटे पानी लाने और ले जाने में बिताने पड़ते हैं। इस कारण उनका स्कूल छूट जाता है। ऐसी व्यवस्था को रोके जाने की आवश्यकता है।

जल उपलब्धता में कमी के कारण दुनिया में अराजकता के हालात पैदा हो रहे हैं। जल की कमी दुनिया भर में पलायन का प्रमुख कारण है और विस्थापित लोग जिन स्थानों पर बसते हैं वहां संसाधनों पर दबाव पड़ता है। यूएन की रिपोर्ट में सोमालिया में एक अध्ययन का हवाला दिया गया है जिसमें विस्थापित लोगों के एक समूह के खिलाफ महिला उत्पीड़न और हिंसा में दो सौ प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी।

रिपोर्टके अनुसार, दुनिया में कम से कम दस प्रतिशत वैश्विक पलायन जल संकट से जुड़ा हुआ है। अब जबकि दुनिया में जलवायु से जुड़ी अनियमितताएं बढ़ रही हैं, इससे जुड़ा पलायन भी बढ़ना तय है। जल संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब देश हैं, जिनके लिए जलवायु परिवर्तन से अनुकूलन के समुचित साधन नहीं हैं। गरीब देशों में ८० फीसदी नौकरियां पानीपर निर्भर होती हैं, क्योंकि यहां रोजगार सेक्टर की निर्भरता कृषिपर होती है, जबकि विकसित देशों में रोजगार की पानीपर निर्भरता 50 फीसदी ही होती है। ऐसे में गरीब देशों में जल संकट से समूची अर्थव्यवस्था में संकट और तनाव खड़ा हो जाता है, जो कि दुनिया में अस्थिरता का कारण बनता है। बढ़ती जनसंख्या और पानी की अधिक खपत की प्रवृत्तियों पर गंभीरतापूर्वक दृष्टिपात करने पर ज्ञात होता है 1900 से वैश्विक तौर पर ताजे जल की खपत छह गुना क्यों बढ़ गई है? ताजे जल की निश्चित मात्रा की बढ़ती मांग से पानी से जुड़े कई विवाद उत्पन्न हो रहे हैं लेकिन अधिकतर जल संबंधी समस्याएं स्थानीय हैं, वैश्विक नहीं। अपने देश में भी गर्मी के मौसम से पहले भारत के 150 प्रमुख जलाशयों की भंडारण क्षमता उनकी कुल क्षमता का केवल 38 प्रतिशत है, जो पिछले दशक की इसी अवधि के औसत से कम है। बेंगलूरू जैसे शहर पहलेसे ही 2600 मिलियन (दस लाख) लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) की माग के मुकाबले लगभग 500 एमएलडी पानी की कमी से जूझ रहे हैं ।

वर्ष 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो प्रति व्यक्ति ००० क्यूबिक मीटर पानी उपलब्ध था। साल 2021 से 2031 के बीच यह 1486 से गिरकर 1267 क्यूबिक मीटर हो जायगा। इसका अर्थ यह है कि कम उपलब्धता के साथ हम पानीके संकट में हैं। चिंता. जनक यह भी है कि जितना कम पानी उपलब्ध होगा, उतना ही वह प्रदूषित भी होता चला जायगा। हमें ४००० अरब क्युबिक मीटर पानी जो बारिशकी कृपासे मिलता है, उसका हम मात्र 1100 क्यबिक मीटर ही उपयोग में ला पाते हैं। अपने देश में 70 फीसदी पानी उपयोग के लिए अयोग्य पाया गया है। यही कारण है कि बोतल बंद पानी का व्यापार लगातार बढ़ता जा रहा है। ध्यतव्य हो कि एक लीटर पानी की बोतल के पीछे तीन लीटर पा्नी खराब होता है और बोतलें प्लास्टिक प्रदूषण भी उत्पन्न कर रही हैं। इस समय धरती पर पानी का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। इसकी चपेट में भारत समेत दुनिया के कई देश हैं । भारत में ऐसे शहर हैं, जहां पानी के लिए हाहाकार मच सकता है। इन पांच शहरोंमें दिल्ली, राजस्थान का जयपुर पजाब का बठिंडा, मुंबई और चेत्नई शामिल हैं जानकारों की माने तो जल. संकट एक राष्ट्रव्यापी मुद्दा है। भारत में दुनिया की आबादी का 18 प्रतिशत है, लेकिन जल संसाध न केवल चार फीसदी हैं। भारत का जो मुख्य जल भंडार हैं, वह इस वक्त पांच वर्षों में अपने सबसे निचले स्तरपर है। नीति आयोगकी एक रिपोर्टके मुताबिक 2030 तक 40 फीसदी भारतीयों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं होगा। रिपोर्ट में चिंताजनक भूजल उपलब्ध ता वाले 21 शहरों दिल्ली, गुरुग्राम, गांधीनमर, जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद, आगरा, इंदौर, अमृतसंर, वेज्योर, चेत्लरई एवं लुधियाना शामिल हैं।

एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली की आबादी 2.4 रोड है। यहां 600मिमी प्रति मिनट वर्षा होती है, जो जरूरतसे काफी कम है। दिल्ली 50 फीसदी पानी की जरूरतोंके लए हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब पर निर्भर है। यदि इन राज्यों ने इनकार कर दिया तो दिल्ली बरबादी के कगार पर पहुंच जायगी। इसी तरह मुंबई समुद्र के किनारे बसा है। यहां भारी मात्रा में बारिश होती है। मुंबई अच्छे जल संसाधनों से समृद्ध है, लेकिन तेजी से हो रहे शहरीकरण और जनसंख्या विस्फोट के सामने जल संसाधन प्रबंधन प्रभावी नहीं हैं। इसलिए आने वाले समय में यहां भी पानी की किल्लत हो सकती है और तो और, भले ही पंजाब में पांच नदियां हैं, लेकिन इसकी कृषि जल खपत वॉटर रिचार्ज की तुलना में बहुत अधिक है। नीति आयोग की रिपोर्ट में पंजाब के कई शहरों पर जल संकट का खतरा बताया गया है। इसे जांचना होगा। पानी की कमी एक मानव निर्मित आपदा है, इसलिए जल संसाधन के कुप्रबंधन को ठीक करना जरूरी है।

शुरू होनी चाहिए पर्यावरणीय मुद्दों को मुख्यधारा में लाने की चुनावी प्रथाएं

राजनीतिक दलों को जलवायु परिवर्तन पर सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए स्पष्ट रूप से कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। राजनीतिक दलों को उन कदमों के बारे में बताना चाहिए जो वे भारत पर ग्लोबल वा. र्मिंग के प्रभाव को कम करने के लिए उठाएंगे। यदि भारत वैश्विक व्यवस्था में अपना उचित स्थान पाना चाहता है, और ष्अमृत कालष में एक सच्ची विश्व शक्ति के रूप में गिना जाना चाहता है, तो जलवायु परिवर्तन कार्यों पर इसके नेतृत्व की मांगों पर नजर रखी जाएगी। मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका पारंपरिक चुनाव तरीकों के पर्यावरणीय प्रभाव पर जोर देने, नवीन पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करने में हो सकती है। पर्यावरण के प्रति जागरूक चुनावी प्रथाओं को अपनाने से भारत को दुनिया भर के अन्य लोकतंत्रों के लिए एक उदाहरण स्थापित करने में मदद मिल सकती है।

संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट ने चिंता पैदा कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार, 2023 को आधिकारिक तौर पर ग्रह के इतिहास में सबसे गर्म वर्ष के रूप में पहचाना गया है। राजनीतिक अभियानों में जलवायु परिवर्तन कार्य योजनाओं को शामिल करके, राजनीतिक नेता मतदाताओं के बीच मुद्दे की गंभीरता और निर्णायक कार्रवाई की अनिवार्यता के बारे में जागरूकता बढ़ा सकते हैं। यह सार्वजनिक चर्चा को जलवायु कार्रवाई को प्राथमिकता देने की दिशा में स्थानांतरित करने और नीति निर्माताओं और जनता के बीच तात्कालिकता की भावना को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। जलवायु परिवर्तन को राजनीतिक अभियानों में एकीकृत करना राजनीतिक दलों को सतत विकास और वैश्विक नेतृत्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है।

डब्ल्यू.एम.ओ. रिपोर्ट सामूहिक सार्वजनिक कार्रवाई शुरू करने को अनिवार्य बनाती है-कुछ-कुछ वैसा ही जैसा कि कोविड-19 महामारी के दौरान हुआ था। इस चुनावी मौसम में, डब्लूएमओ रिपोर्ट का परिणाम न केवल पूरी मानवता के लिए, बल्कि विशेष रूप से सभी राजनीतिक दलों के लिए जागृत होना चाहिए। डब्ल्यूएमओ, संयुक्त राष्ट्र और वैज्ञानिक बिरादरी द्वारा व्यक्त की गई जलवायु परिवर्तन पर चिंता को राजनीतिक दलों को अपनी कार्य योजनाओं को स्पष्ट करने के लिए प्रेरित करना चाहिए।पूर्व-औद्योगिक स्तर से औसत तापमान वृद्धि ँ0.12 डिग्री सेल्सियस की अनिश्चितता के मार्जिन के साथ 45 डिग्री सेल्सियस रही है। तापमान वृद्धि विभिन्न देशों द्वारा तय की गई 5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को तोड़ने के करीब है। डब्ल्यूएमओ की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 स्पष्ट अंतर से सबसे गर्म वर्ष था और जहां कई रिकॉर्ड टूट गए। समुद्र के तापमान में वृद्धि, ग्लेशियर पीछे हटने, अंटार्कटिक बर्फ के आवरण में कमी, ग्रह के चारों ओर समुद्र के स्तर में वृद्धि के रिकॉर्ड।

2023 में दुनिया के महासागरों की गर्मी सामग्री रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई, जो अब तक दर्ज की गई महासागरीय गर्मी सामग्री का उच्चतम स्तर है। महासागरीय धाराओं की एक प्रणाली, अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (एएमओसी) का धीमा होना। वैश्विक औसत समुद्र-सतह तापमान (एसएसटी) 2023 में रिकॉर्ड ऊंचाई पर था, कई महीनों में पिछले रिकॉर्ड महत्वपूर्ण अंतर से टूट गए। वैश्विक महासागर में औसत दैनिक समुद्री हीटवेव कवरेज 32% का अनुभव हुआ, जो 2016 में 23% के पिछले रिकॉर्ड से काफी ऊपर है। गर्मी की लहरें, मूसलाधार बारिश और उष्णकटिबंधीय चक्रवात जैसी चरम मौसमी घटनाओं की आवृत्ति बढ़ गई है। 2023 में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि हुई, नवीकरणीय क्षमता में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 50% की वृद्धि हुई। 18वीं सदी के मध्य से औद्योगिक प्रगति के प्रमुख चालक सभी क्षेत्रों में मशीनीकरण और प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार रहे हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद की अवधि में प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन काफी बढ़ गया है। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से प्रेरित प्रगति का पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता का जलवायु पर भारी प्रभाव पड़ा है। जीवाश्म ईंधन के उपयोग से ग्रीनहाउस गैसों का बड़े पैमाने पर उत्सर्जन हुआ है, जिससे सीधे वैश्विक तापमान में वृद्धि हुई है। भारत को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ने के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करनी चाहिए क्योंकि देश पेरिस समझौते में उल्लिखित लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए काम कर रहे हैं। राजनीतिक दल अपने मंचों पर विशिष्ट नीतियों और कार्यों की रूपरेखा तैयार करके जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों को संबोधित कर सकते हैं। इसके अलावा, भारत में चुनावी मौसम जलवायु परिवर्तन पर चर्चा को बढ़ाने और राजनीतिक दलों को पर्यावरणीय मुद्दों पर उनके रुख के लिए जवाबदेह बनाने का एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करता है। मतदाताओं का अनुमान है कि जलवायु परिवर्तन के बारे में उनकी चिंताएँ बढ़ने पर राजनीतिक नेता अपने नीतिगत एजेंडे में स्थायी समाधानों को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। राजनीतिक अभियान महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चिंताओं पर लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं और जलवायु परिवर्तन कार्य योजनाओं को शामिल करके उन्हें हल करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखा सकते हैं। जैसा कि भारत वैश्विक मंच पर अपनी सही जगह का दावा करना चाहता है और 'अमृत काल' में एक दुर्जेय विश्व शक्ति के रूप में उभरना चाहता है, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने में इसके नेतृत्व की प्रभावशीलता पर बारीकी से नजर रखी जाएगी। राजनीतिक स्पेक्ट्रम के पार, पार्टियां भारत की आर्थिक समृद्धि को आगे बढ़ाने और इसकी आबादी की भलाई में सुधार लाने के उद्देश्य से पहल को प्राथमिकता दे रही हैं। हालाँकि, कार्रवाई योग्य योजनाओं के माध्यम से जलवायु परिवर्तन की केंद्रीय चुनौती से निपटने के ठोस प्रयास के बिना राष्ट्रीय प्रगति के लिए कोई भी व्यापक एजेंडा अपर्याप्त होगा।

प्रियंका सौरभ

उपराष्ट्रपति ने दिलाई सोनिया समेत 15 को राज्य सभा की शपथ

नई दिल्ली । कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने गत दिनों श राजस्थान सांसद राज्य सभा के तौर पर शपथ ग्रहण किया । इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा ने सोनिया गांधी से मुलाकात की । कार्यक्रम के दौरान सोनिया गांधी के अतिरिक्त केन्द्रीय रेलवे मंत्री अश्ली प्रवणन साईत 14 अन्य ने भी राज्य सभा सांसद के तौर पर शपथ ली । नये संसद भवन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड के इन सभी नेताओं को वद और गोपनीयता की शपथ दिलाई ।

सोनिया गांधी ने राजस्थान , अखिनी वैष्णव (ओडिशा) से , कांग्रेस नेता अजय माकन ने कर्नाटक , भाजपा नेता आरपीएन सिह उत्तर प्रदेश भाजपा सदस्य समिक भट्टाचार्या , पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली बाई एस आर सीपी के गोला बाबू . मेधा रघुनाथ रेड्डी से कम वेंकट सुबक रेड्डी ने आंध्र प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वालों के रूप में शपथग्रहण किया । विदित हो कि सोनिया गांधी ने पहली तर राज्य सभा सांसद के तौर प शाळ गयी । वे राज्य सभा राजाधान से निर्विरोध चुनी गई । लम्बे अंतराल के बाद ऐसा हुआ जब नेहरू - गांधी परिवार के किसी सदस्य ने राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लिया है ।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने लगाई बंगाल सरकार को फटकार

कोलकाता । संदेशवाली पकली में कोलकाता हाई कोर्ट ने गत दिनो (गुरुवार को) बंगाल सरकार को कहा कि अगर इस मामले में एक प्रतिशत भी सच्चाई है तो यह शर्मनाक है । द्वारा प्रशासन और सत्तारूढ़ दल इसके लिए शत प्रतिशत नैतिक तौर पर जिम्मेदार है । यह लोगों की सुरक्षा का मागला है।

संदेश खाली के मुख्य आरोपी शाहजहां के खिलाफ पांच जनहित याचिकाओं पर- चीफ जस्टिस टीएमशिव ज्ञानम और जस्टिस हिरण्यभय भद्राचार्य की बेंच सुनवाई की। प. बंगाल की संदेश खालि में महिलाओं के यौन उत्पीड़ 4 और जमीन हड़पने के आरोपी.टी.एम.स. ही एम से, निष्कासित नेता शेख शाहजहां को बंगाल पुलिस ने 29 फरवरी को गिरफ्तार किया था जिसके बाद पुलिस ने उसे सीबीआई को सौप दिया था।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देश का सबसे जिम्मेदार व्यक्ति ने खारिज कर

देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले को देश का सबसे बड़ा और जिम्मेदार आदमी ही यदि खारिज करता दिखाई दे तो किसी दूसरे से कोई क्या उम्मीद कर सकता है? उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई भी प्रणाली पूरी तरह से सही नहीं है और खामियों को दूर किया जा सकता है? उन्होंने यह भी कहा कि इस विषय पर हंगामा करने वाले लोग पछताएंगेँ जाहिर है कि मोदी हैं तो न संविधान बड़ा है और न कोई अदालत। वे सबसे ऊपर थे, हैं और रहेंगे, और ये स्वाभाविक हैँ यदि उनकी सरकार तीसरी बार बनी तो तय मानिये कि इस असंवैधानिक घोषित किये जा चुके 'इलेक्टोरल बॉण्ड ' को ससम्मान संवैधानिक बना देंगे, क्योंकि ये बांड उनकी पार्टी के लिए 'कामधेनु' साबित हुए हैं। निर्माण और विध्वंस दोनों समानान्तर क्रियाएं हैं, कोई देश बनाता है तो कोइ देश बिगाड़ता है। मोदी दोनों काम एक साथ कर रहे हैं। वे अपने सपनों का देश बना रहे हैँ, जिसमें उनके अलावा कोई दूसरा सुप्रीम नहीं है। फिल्म निर्माता मनोज कुमार आज यदि कोई अपनी नई फिल्म बनाते तो उसमें गीत के बोल होते- 'मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में मोदी होते हैं' इस देश को एक मोदी बना रहा है तो दस मोदी बिगाड़ रहे हैं। आज किसी भी राजनैतिक दल में किसी सामाजिक कार्यकर्ता में इतनी क्षमता नहीं है कि वो इलेक्टोरल बांड के मामले में मोदी के पैरवी के कथन को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बताने का दुस्साहस कर सके। खुद सुप्रीम कोर्ट भी शायद उनके वक्तव्य को चुचाप सुनकर अपमान का घूँट पीकर रह जाएगा।

इलेक्टोरल बांड के समर्थन में सीना ठोंक कर खड़े होना कोई आसान बात नहीं है। ये वह शौर्य हैं जिसके लिए मोदी को परमवीर चक्र दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की चुनावी बाण्ड योजना के कारण ही चंदे के स्रोतों और इसके लाभार्थियों का पता लगाया जा सका। उनका सवाल था कि क्या इसके पहले किसी चंदे की जानकारी हो सकती थी। आज जानकारी उपलब्ध हुई है तो उसकी वजह इलेक्टोरल बॉण्ड है।

वे जिस हिकमत अमली से गलत को सही और सही को गलत साबित करने में माहिर हैं, वैसा देश में आज तक कोई दूसरा नेता नहीं है।

मोदी जी जैसा दमखम पूर्व के किसी प्रधानमंत्री में था ही नहीं। इंदिरा गाँधी में भी नहीं, जबकि वे तो तबकी भाजपा जनसंघ के लिए दुर्गा थीं। इंदिरा जी को भाजपा यानि जनसंघ, ने उदारतापूर्वक 1971 के भारत-पाक संग्राम के बाद बांग्लादेश बनवाने के लिए दुर्गा कहा गया था। कांग्रेसियों को चाहिए कि वे मोदी को देश को जबरन विश्वगुरू बनाने के लिए तांडव करने वाला 'शिव' कहकर उऋण हो जाए। कांग्रेस द्वारा पिछले साढ़े छः दशक में कितना कुछ किया था, उसे एक दशक में ही मोदी ने ध्वस्त कर दिया।

पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित किए जा चुके चुनावी चन्दा बॉड्स को लेकर लम्बा वक्त गुजरने के बाद प्रधानमंत्री का भाषण सामने आया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गर्व के साथ ही नहीं बल्कि सीना ठोक कर कह रहे हैं कि जो लोग आज इलेक्टोरल बॉडस को लेकर नाच रहे हैं, वे कल पछतायेंगे। मोदी जी उनके इस दमखम स यही लगता है कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते। आप भी परेशन है और एक लेखक के नाते मैं भी परेशान हूं। क्योंकि हर बात अब राजनीति से शुरू होकर राजनीति पर ही समाप्त हो रही है। जब कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि हर बात में राजनीति नहीं देखना चाहिए। मैं कहता हूं कि हर दिन मुझे मोदी का नाम सुमरना न पड़े। लेकिन दुर्भाग्य से मोदी का नाम लिए बिना कोई बात नहीं बनती है और न बिगड़ती है। मोदी यानी 56 इंच का सीना मोदी जी यानि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।

जैसी कहावत। उनकी नजर में इलेक्टोरल बॉड्स आज भी गंगाजल की तरह पावन है। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान जब उने ये पूछा गया कि क्या चुनावी बॉण्ड डेटा से सत्तारूढ़ भाजपा को झटका लगा है? तो मोदी ने कहा, मुझे बताइए कि हमने ऐसा क्या कर दिया कि मैं इसे एक झटके के तौर पर देखूं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि जो इसे (बॉण्ड के विवरण) को लेकर हंगामा कर रहे हैं और इस पर गर्व कर रहे हैं उन्हें पछतावा होगा।

विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुए खुलासे का हवाला देते हुए सरकार के प्रति हमलावर रुख अपना रखा है। न्यायालय ने गुमनाम तरीके से चंदा देने को असंवैधानिक घोषित करते हुए चुनावी बाण्ड से संबंधित सभी जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश दिया था। आपराधिक जांच का सामना कर रही कई कंपनियों ने बड़ी मात्रा में बॉण्ड खरीदे थे। मोदी जी और उनकी पार्टी भाजपा अब इसी मुद्दे को लेकर जनता की अदालत में खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है। बारी अब जनता की है देखना है कि जनता की अदालत में इलेक्टोरल बाण्ड्स का मामला क्या गुल खिलाता है?कोई प्रधानमंत्री से सवाल नहीं कर सकता, क्योंकि इस देश में सवाल करना देशद्रोह करना है।

अन्यथा उनसे पूछा जा सकता था जिस तरह से इलेक्टोरल बांड खरीदने और दान करने के लिए गोपनीयता बरतने की व्यवस्था की गयी जिसके तीन कानूनों में संशोध न किया गया, क्या उससे पहले किसी और बॉड्स के लिए की गई थी क्या? इलेक्टोरल बॉण्ड के जरिये जो खुलासा हुआ है यदि सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता तो क्या सम्भव था? लेकिन हमारा असमंजस ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट की जय बोले या मोदी की जय बोलें। सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा डर नहीं लगता लेकिन मोदी जी से लगता है। क्योंकि वे अदावत करने में माहिर हैं। वे खास आदमी से ही नहीं आम आदमी से भी अपना हिसाब बराबर कर सकते हैं।

समीक्षा बैठक संपन्न

गोरखपुर। मण्डलायुक्त अनिल ढींगरा ने आयुक्त सभागार में रेलवे, सेतु निगम एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुये जनपद में निर्माणाधीन बरगदवां ओवरब्रिज, ओंकारनगर-बालापार ओवरब्रिज, गोरखनाथ ओवरब्रिज की प्रगति की जानकारी ली।

उन्होंने बरगदवां उपरगामी सेतु की समीक्षा करते हुये सेतु निगम एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियो को निर्देश दिया कि पुल के निर्माण कार्य को रेलवे से समन्वय करते हुये तेजी से कार्य कराया जाये और निर्माणकार्य में आ रहे अवरोध को तत्काल हटाया जाये।

मण्डलायुक्त ने ओंकारनगर-बालापार ओवरब्रिज, गोरखनाथ ओवरब्रिज की समीक्षा करते हुये निर्देश दिया कि कार्यो में तेजी लायी जाये।

आज मैं फिर से लिखूंगा

था रहा मैं जूझता जो द्वंद जीवन में मिले थे
थी कलम विश्राम में
पर मैं पुनः फिर से लिखूंगा..।।
थे पड़े सूने जो पन्ने
मैं पुनः उनको भरूंगा
टूटकर फिर से उठा हूं
आज मैं फिर से लिखूंगा..।।
था मुझे संबल मिला जब भी कलम थी साथ में
साथ साथी का मिला
फिर से उमंगों को लिखूंगा..।।
मैं गिरा था हार कर
अपनों ने था धक्का दिया
चीटियों से सीख लेकर
मैं पुनः हिम्मत लिखूंगा..।।
चोट जब अपनों से खाओ
जख्म दिखलाना है मुश्किल
है गुलाब कांटों में खिलता
फिर से मैं खुशबू लिखूंगा..।।
आज मैं फिर से लिखूंगा..।।
आज मैं फिर से लिखूंगा..।।

विजय कनौजिया
ग्राम व पत्रालय-काही
जनपद-अम्बेडकर नगर-225132
(उत्तर प्रदेश)

आदमी का चरित्र

कैसा है आदमी कैसा उसका चरित्र
देखने में भोला भाला काम हैं विचित्र
दिमाग और सोच में भरी है गंदगी
फिर भी अपने आप को कहता है पवित्र
आदमी आदमी में फर्क है
कोई है पैसे वाला कोई है फकीर
जो भी जिसको जीवन में मिला
सबकी अपनी अपनी है तकदीर
कोई दूसरे की सेवा में रहता है खुश
दूसरों का हक मार जाता है कोई
बड़ा बनकर भी कोई जमीन से है जुड़ा रहता
सफलता मिलते ही अहंकार में डूब जाता है कोई
चेहरे की मासूमियत से
किसी का पता नहीं चलता
किसी के दिल में क्या है यह तो वही जाने
काम निकल जाने पर कोई पहचानता नहीं
सामने देखकर भी बन जाते हैं अनजाने
कैसा बन गया है आदमी का चरित्र
हर तरफ है धोखा ही धोखा
ऊन निकालने की फिराक में रहते हैं भेड़ से सारे
बस मिलना चाहिए किसी को भी मौका

रवींद्र कुमार शर्मा
घुमारवीं,
जिला बिलासपुर हि प्र

समाचार पत्र विक्रेता संघ का होली मिलन संपन्न

गोरखपुर (जीकेबी)। समाचार पत्र विक्रेता संघ के तत्वावधान में नगर निगम पार्क लक्ष्मी बाई मूर्ति के पास रविवार को उमाशंकर मझवार की अध्यक्षता में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान फूलों की वर्षा कर फूलों की होली खेली गयी। सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। मुख्य अतिथि राममूर्ति विशिष्ट अतिथि महेन्द्र सिंह राणा, विशिष्ट अतिथि केपी चौधारी बसपा नेता पंकज धर द्विवेदी (संपादक घूंघट की बगावत), हरिराम निषाद, रामाज्ञा निषाद ने सभी से गले मिलकर स्वागत किया। अंत में राकेश कुमार निषाद ने सभी को जलपान कराया। इस अवसर पर दीपचंद मझवार, राजेश साहनी, केपी चौधरी, राजन पासवान, कल्ला चौहान, तीरथ सिंह श्रेष्ठ, रामसजीवन निषाद, धर्मेंद्र कुमार, विनोद तिवारी, सुनील कुमार गुप्ता, आत्मा प्रसाद मझवार, आदित्य यादव, सत्येंद्र यादव किसान नेता, सुभाष चंद्र मझवार, राजकुमार मझवार, चंदन मझवार, सुरेंद्र कुमार मझवार, ओमप्रकाश मझवार, विजय कुमार गुप्ता, हरिलाल मझवार, रवि कुमार, राहुल गुप्ता, उर्फ मुन्ना, निहाल खान व अमरनाथ गुप्ता सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

'छायावाद और स्वातंत्र्य चेतना' विषयक विशिष्ट व्याख्यान

छायावादी साहित्य तत्कालीन परिस्थितियों से उद्भूत : प्रो. ओमप्रकाश

गोरखपुर (जीकेबी)। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर के हिन्दी विभाग द्वारा **'छायावाद और स्वातंत्र्य चेतना'** विषयक विशिष्ट व्याख्यान का आयोजन किया गया। जिसके मुख्य वक्ता डॉ.नन्दन, सहायक आचार्य महात्मा गाँधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी बिहार रहे। विषय को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने भारतेन्दु युग के कालगत साहित्यिक बोध पर बोलते हुए छायावाद की श्याम राजनैतिक, सांस्कृतिक स्वरूप विस्तृत चर्चा किया। उन्होंने आगे कहा कि छायावाद के मूल में जयशंकर प्रसाद और सूर्यकान्त त्रिपाठी निरालाश के साहित्य का अध्ययन कर छायावाद और स्वातंत्र्य चेतना को समझा जा सकता है। जो कविता आध्यात्म की सीढियाँ चढते हुए प्रगति करती हैं वह कभी पलायनवादी नहीं हो सकती स्वतंत्र हो सकती है। प्राणों की आहुति देकर ही देश स्वतंत्र हो सकता है, जो भारत की परम्परा में रहा है। दुनिया के किसी भी देश के इतिहास में आज तक सबसे ज्यादा बलिदान स्वतन्त्रता के लिए ही हुआ है। भारत की पहचान जिन मूल्यों के कारण रही है वह हमारी संस्कृति ही है ।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि छायावादी कवियों में अतीत गौरव की अभिव्यक्ति, स्वाधीनता की चेतना; राष्ट्र-प्रेम, त्याग और बलिदान, अस्मिता की खोज एवं प्रकृति चित्रण का वर्णन है। छायावादी साहित्य तत्कालीन परिस्थितियों से उद्भूत है जहां भारतीय जन मानस में स्वतंत्रता की आकांक्षा, राष्ट्र-प्रेम जैसे मूल्य व्याप्त थे । कार्यक्रम का विषय प्रवर्तन प्रो. नित्यानन्द श्रीवास्तव प्रभारी हिन्दी विभाग, संचालन डॉ. विभा सिंह तथा आभार ज्ञापन डॉ. अदिति दुबे ने किया।

लघु शोध लेखन समस्या एवं समाधान विषयक कार्यशाला संपन्न

गोरखपुर। श्रीमती द्रौपदी देवी पीजी कॉलेज रुद्रपुर में गत दिनों लघु शोध लेखन: समस्या एवं समाधान विषयक एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। दो सत्रों में आयोजित इस कार्यशाला का उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता प्राचार्य डॉ. राजेश कुमार धर दूबे ने किया। कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में कार्यशाला का केन्द्रीय व्याख्यान प्राचार्य राजेश धर ने शोध लेखन के विविध आयामों पर व्यापक चर्चा की। राजनीति विज्ञान के प्रवक्ता डॉ. राजनाथ ने शोध प्रविधि पर सविस्तार प्रकाश डाला। डॉ. सुषमा शुक्ल ने मानविकी के तथ्य संकलन की तथ्य संकलन की प्रविधि की चर्चा करते हुए प्रश्नावली आदि तैयार पर चर्चा की। उसमें डॉ. एनके सिंह, डॉ. अजय सिंह श्रीराम सिंह ने भूमिका का निवर्तन किया। डॉ. सत्येन्द्र कुमार साहित्य में शोध विषयक समस्याएं, डॉ. अविनाशपति त्रिपाठी शोध में पूर्व शोध की भूमिका, डॉ. विनय कुमार पासवान ने शोध के लिए सांख्यिकीय आंकड़ों का महत्व, डॉ. लता श्रीवास्तव साहित्य में शोध प्रविधि, डॉ. नीरज सिंह भूगों में शोध प्रविधि, डॉ. कमलेश यादव शोध परिकल्पना अर्थ तथा उपयोगिका डॉ. आलोक रंजन शोध में उपसंहार इत्यादि विषयों पर चर्चा की। कार्यशाला की समक्षा तथा उपादेयता प्राचार्य डॉ. राजेशकुमार धर दूबे ने, विषय प्रवर्तन आयोजन सचिव डॉ. आलोक रंजन भारद्वाज एवं संचालन सुश्री-जया चौधरी ने किया।

एक कोरी प्रेम कथा फिल्म हुई रिलीज

गोरखपुर। सुगंध फिल्म्स और केनिलवर्थ फिल्म्स एलएलपी की फिल्म एक कोरी प्रेम कथा दर्शकों के बीच उत्साहपूर्ण माहौल में गत दिनों रिलीज कर दी गई। एक कोरी प्रेम कथा जैसा कि नाम है वैसी ही फिल्म की प्रेम कहानी भी। विवाह के समय दुल्हन के वर्जिनिटी टेस्ट जैसी उभरती नई कुप्रथा पर आधारित है। इस फिल्म की कहानी समाज के उस पक्ष को उजागर करती है जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। फिल्म ने समाज में पनपने वाली एक नए प्रकार की कौमार्य परीक्षण (वर्जिनिटी टेस्ट) जैसी कुप्रथा को उजागर करते हुए महिलाओं केउस दर्द को समाज के सामने प्रस्तुत किया है।

ईद के पर्व के मद्देनजर खरीदारी करती महिलाएं

भारत में बढ़ती गरीबी और अमीरी की खाई

पूरे देश में आर्थिक विकास का ढिंढोरा पिट रहा है। देश में सरकार के विज्ञापनों और बनती सड़कों, एक्सप्रेस वे एयरपोर्ट को देखा जाये तो लगता है देशके अन्दर विकास की आंधी आ गई है। देश को तीसरी अर्थव्यवस्था का सपना भी दिखाया जा रहा है। लेकिन जैसे ही हम गांवों और कस्बों की ओर रुख करते हैंऔर हकीकत को करेदने की कोशिश करते हैं आर्थिक मुसीबतें रुकने का नाम ही नहीं लेती हैं। अभी हालही में आयी वल्ड इनडक्लेलिटी लैब यानी आर्थिक असमानता रिपोर्ट यह दर्शाती है कि दुनिया भर में आर्थिक असमानता में भारत भी शामिल है जहां आर्थिक असमानता तेजी से बढ़ी है अमीर और अमीरहुए हैं और गरीब और भी गरीब हुए हैं। अमीरी और गरीबी की खाई जो 1991 में उदारवादी व्यवस्था के अपनाने के साथ गहरी और चौड़ी होनी शुरू हुई थी वह निरन्तर बढ़ती ही जारही है। सरकार इस रिपोर्ट को भले ही झुठला `लेकिन वरह भी अच्छी तरह से समझती है कि आखवरएक सौ चालीस करोड़ की आबादी वाले दॅशि में 81करोड़ 35 लाख लोगों को मुफ्त पांच किलो राशनउसे क्यों देना पड़ रहा है जबकि वह नीति आयोगकी रिपोर्ट के माध्यम से दावा करती है कि गरीबीकी रेखा के नीचे सिर्फ पांच प्रतिशत लोग रह गए हैं। लगभग 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए हैं। विश्व आार्थिक असमानता की इस रिपोर्ट का निष्कर्ष यही है कि वर्ष 2022-2023 में भारत में गरीबी और अमीरी की खाई इस हद तक बढ़ गई है कि जो गुलाम भारत 1922 के दशक से अभी अधिक है।

यदि हम रिपोर्ट के आंकड़ों पर न भी जायें तोभी देश में जिस प्रकार से अरबपति खरबपतियों कीसंख्या बढ़ रही है उसी अनुपात में निचले स्तर परलोगों के जीवन में आर्थ और सम्पत्ति नहीं अ पारही है।

कोरोना काल में किस प्रकार घंटे-घंटे करोड़ोंकमा रहे थे जब सब कुछ बंद था लोगों के खाने केलाले पड़े हुए थे। इससे तो यही लगता है कि सरकारकी नीतियों में ही वह खामियां हैं जिसमें जब राष्ट्रीयआय जोड़ी जाती है तो एक तरफहजार कमाने वालीकी भी उसमें जुड़ती है और अरबपति की भी उसम. जुड़ती है तो यह पैमाना सही कैसे हो सकता है। एकतरह लोग आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं वहीं दूसरीओर तिकड़म से लोग पैसे बनाने में लगे हुए हैं। जब टैक्स लगाने की बारी आती है तो जो सबसेअधिक धनी होते हैं उन पर रियायत बरती जाती है।कारपोरेट टैक्स में करमी रहती है और आम आदमीतो जीएसटी कोई भी सामान खरीद कर देता है जिसकीसंख्या आाबादी में काहीं अधिक है। लेकिन उसके टैक्सको महत्व नहीं दिया जाता है आयकर चुकाने वाले हीअपने को टैक्सपेयर समझते हैं। आखिर धन धरतीके असमान बंटवारे और आय के वितरण के मानकीके लिए जिम्मेदार तो वह नीतियां ही हैं जिनसे यह असमानता तेजी से बढ़ती जा रही है और हम सपने देखने में लगें हुए हैं।

यह सही है कि लोगों के रहन-सहन खर्च करने केतरीकों में बड़ा परिवर्तन पिछले तीन दशकों में आयाहै। यही नहीं कमाने और खर्च करने के तरीके बदलेहैं। लोग कर्ज लेकर भी खर्च करने के लिए तैयार बैठेरहते हैं। इसका मतलब यह तो नहीं कि वह अमीर होगए हैं या अमीरों के बराबर हो गए हैं।

एक तरफतोदेश में काम के अवसरों की भारी कमी है वहीं दूसरीओर लोग कम वेतनभत्तों पर काम करने को मजबूरहैं। बाजार उन्हें अधिक खर्च करने के लिए मजबूरकर रहा है।

सरकारी नौकरियो में ही अब श्रेणी केवेतनमान वाले लोग एक ही पद और कार्य को कररहे हैं। निजी क्षेत्र में रोजगार और उद्योग धंधों में भीकार्यरत लोगों की स्थिति लगभग इसी प्रकार है।

देश के अन्दर सर्विस सेक्टर बढ़ा है। देश में बहुत सीसड़के बन रही हैं अमीरों की संख्या बढ़ रही है लेकिनआबादी और प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो आज भीयदि 81 करोड़ लोग मुफ्त राशन के लिए लाइन मेंलग रहे हैं तो इसका लक्षण तो सामने ही दिख रहा है।कि आय और सम्पत्ति का कितना असमान विभाजनहै जिसके कारण अमीर और आमीर और गरीब औरगरीब होता जा रहा है। यह पांच किलो के राशन से वर्तमान में उसके जीवन की बुनियादी जरूरत भोजन में सहूलियत मिल सकती है लेकिन इससे भविष्य संवर जाएगा ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है।

मेरा भारत महान

चंद्रयान पहुँचा चंदा पर,तीन रंग फहराये।
शान बढ़ी,सम्मान बढ़ गया,हम सारे हर्षाये।।
जीरो को खोजा था हमने,आर्यभट्ट पहुँचाया।
छोड़ मिसाइल शक्ति बने हम,सबका मन लहराया।।
सबने मिल जयनाद गुँजाया,जन-गण-मन सब गाये।
शान बढ़ी,सम्मान बढ़ गया,हम सारे हर्षाये।।
मैं महान हूँ,कह सकते हम,हमने यश को पाया।
एक महागौरव हाथों में,आज हमारे आया।।
जिनको नहीं सुहाते थे हम,उनको हम हैं भाये।
शान बढ़ी,सम्मान बढ़ गया,हम सारे हर्षाये।।
जो कहते थे वे महान हैं,उनको धता बताया।
भारत गुरु है दुनिया भर का,यह हमने जतलाया।।
शान तिरंगा-आन तिरंगा,गीत लबों पर आये।
शान बढ़ी,सम्मान बढ़ गया,हम सारे हर्षाये।।
अंधकार में किया उजाला,ताकत को बतलाया।
जो समझे थे हमको दुर्बल,उन पर भय है आया।।
जोश लिये हर जन उल्लासित,हम हर दिल पर छाये।
शान बढ़ी,सम्मान बढ़ गया,हम सारे हर्षाये।।
ज्ञान और विज्ञान रचे हम,हमने शशि को पाया।
आशाओं का सूरज दमका,हमने नवल रचाया।।
नया और अनुपम-मंगलमय,विजय-ध्वजा फहराये।
शान बढ़ी,सम्मान बढ़ गया,हम सारे हर्षाये।।

प्रो(डॉ)शरद नारायण खरे

बेरोजगारी समस्या ही नहीं अपितु चुनौती भी

वर्तमान समय में देश में बेरोजगारी अधिक है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। यह देश की समस्या ही नहीं अपितु बड़ी चुनौती भी है। बेरोजगार युवाओं की ओर देखें ती इनकी तीन श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी में वे युवा आते हैं जो शिक्षित और योग्य हैं और नौकरी की तलाश में दिन-रात एक किए हैं लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिल रहा है, दूसरे स्थान पर वे हैं जो नौकरी तो करना चाहते हैं लेकिन प्रयास नहीं करते और तीसरे स्थान पर ऐसा युवा वर्ग है जो नौकरी करना ही नहीं चाहता इनमें सबसे दयनीय स्थिति पहले वर्ग की है जो शैक्षणिक और तकनीकी रूप से कुशल है लेकिन नौकरी से वंचित हैं और नौकरी की लालच में धोखाधड़ी और शोषण के शिकार होते हैं। जो युवा अच्छी नौकरी और सुविधाओं की लालच में कमाने के लिए विदेश जाते हैं अथवा भेजे जाते हैं उनकी दुर्दशा रूह कंपा देने वाली है।

ऐसे ही कम्बोडिया में तीन महीने से फंसे लाए गए 250 भारतीयों के खुला से रोंगटे खड़ा कर देने वाला है । इन लोगों को दिन में 12 घण्टे काम करने पर मजबूर किया गया और जबरन साइवर फ्रॉड का काम कराया गया। इसमें लगभग पांच सौ करोड ठगी करने का अनुमान है। अमानवीयता की सारी हदें उस समय पार हो गईं जब कम्बोडिया पहंचे लोगों को टारगेट पूरा नहीं होने पर भूखा भी रखा गया। यह दिल दहला देने वाला कृत्य शर्म को भी शर्मसार करने वाला है।

केन्द्र सरकार कम्बडिया में अब भी फंसे लगभग पांच हजार लोगों को वापस लानें का प्रयास कर रही है, जिन्हें उनके मर्जीके खिलाफ रोका गया है। दुर्दशा का दंश झेल रहे इन लोगों के प्रति हर भारतीय की संवेदना और दुआ उनके साथ है। विश्व समुदाय को भी इसे संज्ञान में लेते हुए सभी फंसे भारतीयों को मुक्त कराने के लिए आगे आना चाहिए।

काश मैं चरित्रहीन होती

सुनो!मुझे कुछ सुनाई दिया,
देखो!मुझे कुछ दिखाई दिया।
पर तुम्हें नहीं?
इसलिए कहती हूँ सामान्य
नहीं हूँ मैं,विशेष भी नहीं
इन दोनों परिचयो से मुक्त हूँ।
जानने के इच्छुक हो मुझे
मेरे अंत:करण को तो?
आओ चिर परिचित कराती हूँ
स्वयं से।किंतु
तुम्हें भी सामान्य और विशेष से
मुक्त होना पड़ेगा।
मूंद लो ये दिखावे वाले नेत्रों को,
जागृत करो अपनी इन्द्रियों को
अब आदेश करती हूँ
स्वयं से भेंट करने का
ध्यान केंद्रित करो
मेरे अंत:करण पर!
देखो मेरे लघु हृदय में!
कितना भव्य और विशाल
मंदिर स्थापित हो रखा है।
अब स्वयं के हृदय को
गंगाजल से पवित्र करो।
क्योंकि इस मंदिर का कपाट
इतनी सरलता से नहीं खुलेगा।
देखो कितने असंख्य दीप
मैंने प्रज्वलित कर रखे हैं....
इन दीपों से दिव्य रोशनी
प्रस्फुटित हो रही है
जिसे तुम्हारे सामान्य नेत्र
बर्दाश्त नहीं कर पाते।
देखो उसमें एक देवता की
मूर्ति भी स्थापित है जो
मन देवी के देवता हैं!
सुनो! इस मंदिर के विशाल
घंटियों,शंखों के नाद को
मन देवी के मंदिर में
तुम्हें ऐसे-ऐसे पुष्प मिलेंगे
जो अन्यत्र दुर्लभ हैं।
जिनकी सुगंध से संपूर्ण मंदिर
सुगंधित हो रखा है
इस मंदिर में चढ़े हुए फल
और प्राप्त फल भी।
अन्यत्र दुर्लभ हैं
क्योंकि यह मन देवी के
अंत: करण का मंदिर है
मन देवी मंदिर है।

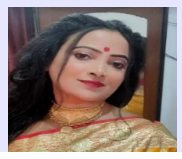

मांडवी सिंह
कुशीनगर-
उत्तर प्रदेश

रंगमंच को समृद्ध करने का बेमिसाल काम करने वाले आगा हश्र

आगा मुहम्मद शाह हश्र काश्मीरी एक ऐसी शख्सयत हैं, जिन्होंने भारतीय रंग मंच में नाटककारों को मान-सम्मान दिलाने का बेहतरीन काम किया। उनका नाम पारसी रंगमंच के बड़े ड्रामा निगारों में शुमार किया जाता है। अरबी, फरसी, उर्दू, अग्रेजी, गुजराती, बांग्ला, संस्कृत आदि कई जबानों के जानकार आगा हश्र थिएटर से रूमानियत और उसके जानिब हद दर्जे की दीवानगी के चलते हालाकि आला तालीम से महरूम रहे, लेकिन अपने शौक और स्वाध्याय से उन्होंने भरत मुनि के नाट्य शास्त्र, भारतीय लोक नाद्य और यूरोपियन रंगमंच के इतिहास और वहां के प्रमुख नाटककारों विलियम शेक्सपियर, शेरेटन, हेनरी आर्थर जोन्स, डब्ल्यू टी माट्रिफि के नाटकों का विशद एवं गहन अध्ययन किया।

आगा हश्र काश्मीरी का दौर, वह दौर था जब देश में आज की तरह सर्व सुविधासम्पत्र स्थाई थिएटर हॉल नहीं थे। पारसी थिएटर कम्पनियां शहर -दर- शहर खुले मैदान और मेलों में ओपन थिएटर करती थीं। आगा हश्र के नाटकों को देखने के लिए लोगों में गजब की दीवानगी थी।

आगा हश्र काश्मीरी को नौजवानी से ही शेरो-शायरी और ललित कलाओं से लगाव था। उन दिनों बनारस में जब भी पारसी थिएटर का मंचन होता, वे जरूर नाटक देखने जो। आगा हश्र काश्मीरी का पहला नाटक मुरीद-ए-शक था। यह डामा शेक्सपियर के अविन्टर्स टेल पर आधारित था। अल्फ्रेड कम्पनी के लिये लिखा, यह नाटक इस कदर मशहूर हुआ कि नौ महीने में इसके साठ मंचन हुये। श्मुरीद-ए-शकश से नाटक कंपनियों ने उनके हुनर का लोहा मान लिया। जब आगा में हश्र के ड्रामे स्टेज पर आए, तो कम्पनी के मालिकों ने महसस किया कि इस नौजवान ड्रमाटिस्ट के ड्रामों में कोई न कोई ऐसी बात है, जो देखने वालों को अपनी तरफखींचती है। हर अच्छी कंपनी की कोशिश होती थी कि आगा हश्र उनके लिए ड्रामे लिखें । जिस कंपनी के साथ हुआ उसके दिन फिर गए।

साल 1910 से 1932 तक का दौर, आगा हश्र काश्मीरी का सुनहरा दौर था। इस दौर में उन्होंने हिन्दी, उर्द दोनों ही भाषाओं के प्रमुख नाटकों की रचना की। पारसी रंगरमंच के लिये उन्होंने जिन नाटकों की रचना की उनमें शास्त्रीय, लोक, यथार्थवादी, धार्मिक-पौराणिक ग्रन्थों, ऐतिहासिक कथानकों और अंग्रेजी रंगमंच के तत्वों का अद्भुत मिश्रण मिलता है। भारतीय जीवन दर्शन, इतिहास, हिन्दुस्तानी रीति -रिवाज और सुभ्यता-संस्कृति उनके नाटकों में साफ परिलक्षित होते हैं। सदियों से भारतीय जनमानस के चेतन और अवचेतन में अन्त. निहित धार्मिक, पौराणिक ग्रन्थों के कथानकों को उन्होंने खास तौर से अपने नाटकों का विषय बनाया। उनका नाटक श्सीता वनवासश रामायण और भीष्म प्रतिज्ञा- महाभारत पर आधारित थे। वहीं नाटक श्भगीरथ गंगा उनके संस्कृत ज्ञान का अनुपम उदाहरण है। आलोचकों ने प्रचारित किया कि हिन्दी के डामें उन्के लिखे नहीं है। वे हिंदी जबान से नावाकिफ है, लिहाजा इतने अच्छे हिंदी नाउक लिख ही नहीं सकते। इसका जवाब उन्होंने नाटक के शो के पहले तकरीक्न दो घटे तक लगातार हिंदी में तकरीर की, जिसमें एक भी शब्द उर्दू श्स फरसी का नहीं था।

आग हश्र काश्मीरी को नौजवानी से ही शेरो-शायरी और ललित कलाओं से लगव था। उन दिनों बनारस में जब भी पारसी थिएटर का मंचन होता, वे जरूर नाटक देखने जाते। आग हश्र काश्मीरी का पहला नाटक मुरीद-ए-शक था।

'बिल्वमंगल', 'मधुर मुरली', 'भारत रमणी', 'भीष्म', 'प्राचीन और नवीन भारत', 'सूरदास', 'लवकुश', 'हिन्दुस्तान', औरत का प्यार, 'आंख का नशा 'भारतीय बालक', 'धर्मी बालक', 'दिल की प्यास, 'पाक दामन, दोरंगी दुनिया उर्फमीठी छुरी, 'वन देवी' आगा हश्र काश्मीरी के वे हिंदी नाक हैं, जो काफी मशहूर हुए। हिन्दी नाटकों के अलावा उर्द्नाटक रुस्तम-सोहराब अपने जीवंत और सशक्त को भी उन्तेने फर्म, तकनीक, भाषा, विषयवस्तु के स्तर पर नये क्षितिज तक पहुंचाया। पारसी रंगमंचपर शुरू से ही शेक्सपियर के नाटकों का असर था और आगा हम्र काशमीरी भी इससे अछते नहीं रहे। सच बात तो यह है कि उनके कई नाटक शेक्सीपयर के प्रसिद्ध नाटकों के अनुवाद, रूपांतर, छायानुवद, भावानुवाद थे। नाके 'सैद- ए-हवस -किंग जॉन, 'बज्म-ए-फानी' -रोमियो एंड जुलियट, श्दिल फोश मचेंट आफ वेनिस, श्शहीद-ए-नाजश -मेजर फॉर सेजार मार-ए-आसीन औथेलो, सफेद खून-किंग लियर, ख्जाब-ए-हस्ती मेकबेथ पर आधारित। आगा हश्र काश्मीरी की निजी जिंदिगी पर शेक्सपियर का खासा असर था। इसी वजह से आगे चलकर जब उत्होंने साल 1919 में अपनी ड्रामा कंपनी बनाई, तो उसका नाम भी शेक्सपियर के ही नाम पर श्इंडियन शेक्सपियर थिएट्रिकल कंपनी ऑफ कलकत्ता रखा। आगा हश्र काश्मीरी के नाटकों में ऐतिहासिक कथानक राजसी दरबार और सियासती दांव-पेंच, षडयंत्र, कूटनीति आदि तमाम तत्व शेक्सपियर के नाटकों की ही देन हैं। बावजूद इसके अपने नाटकों को उन्होंने जिस तरह भारतीय परिवेश, वेशभूषा और हिन्दुस्तानी भाषा में ढाला, वह वाकई तारीफ के काबिल है। जिंदगी के आखरी दिनों में लिखा आगा हश्र का ऐतिहासिक नाटक रुस्तम-सोहराब फरसी के प्रसिद्ध कवि फिरदौसी के ऐतिहासिक एवं राष्ट्रीय महाकाव्य श्शाहनामाश पर आधारित है। नाटक यहदी की लड़की, खूबसूरत बला, सीता वनवास, मशारिकी हूरश, असीरे-हिर्स और आगा हश्र काश्मीरी के कई नाटक उनकी जिंदगी में अप्रकाशित रहे, जिनका प्रकाशन बाद में हुआ। अपने नाटकों के प्रकाशन से ज्यादा, उन्हें मंचन पर विश्वास था। नाटकों के प्रकाशन पर उनका कहना था, ला हौल विला.. . आगा हश्र काश्मीरी के ड्रामें, चीथड़ों पर छपें। बगैर इजाजत के इधर-उघर से सुन-सुनाकर छाप देते है।

आगा हश्र काश्मीरी ने अपनी जिंदगी में करीब सत्ताईस नाटक लिखे। रंगमंच में उन्होंने हमेशा नये-नये प्रयोग किए। उनके नाटय लेखन से पहले नाटक, पूरी तरह काव्यमय होते थे और उनमें अनेक गानों का समावेश होता था। आगा हश्र काश्मीरी ने नाटक में गद्य को महत्व दिया। रंगमंच को चुटीली, मुहवरेदार भाषा दी।

यही नहीं उन्होंने पुराने नाटकों की रंग शैली तथा भाषा को बदल कर आधुनिक रंगमंच की नींव डाली। देशकाल, सामाजिक समस्याओं और अवाम के मिजाज को समझकर अपने नाटकों की रचना की। नाटकों से मनोरेंजन के साथ-साथ सामाजिक, सियासी पैगाम देने की कोशिश की। अपने नाटकों पर उनका कहना था, 'मेरे नाटक देखकर लोग रोते-धोते हुए नहीं, बल्कि मुस्कराते हुए एक संदेश लेकर जायें। आगा हश्र काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से स्वर्ण पदक पाने वाले वे अकेले मुस्लिम लेखक थे। आगा हश्र काश्मीरी बहुत उम्दा शायर भी थे।

साफ सुथरी राजनीति के क्या यही मायने

ऐसे तमाम उदाहरण दिए जा सकते हैं जिसमें नेता जमानत पर बाहर आकर राजनीतिक वातावरण को स्वच्छ करने की बात करते हैं। क्या वास्तव में ऐसे राजनेता देश के राजनीतिक वातावरण को सकारात्मक दिशा देने का सामर्थ्य रखते हैं। कदाचित नहीं।

भारतीय राजनीति में ऐसे कई उदाहरण दिए जा सकते हैं, जो आज भी नैतिकता के आदर्श हैं। लेकिन आज की राजनीति को देखकर ऐसा लगने लगा है कि नैतिकता की राजनीति दूसरा तो अवश्य करें, पर जब स्वयं को नैतिकता की कसौटी पर परखने की बारी आए तब नैतिकता के मायनों को बदल दिया जाता है। भारतीय राजनीति में राजनेताओं पर आरोप लगने पर कई लोगों ने अपने पद को त्याग दिया था, दिल्ली के शराब घोटाले के मामले में मु ख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने भारतीय राजनीति को अलग राह पर ले जाने का उदाहरण पेश किया है, हालांकि इस उदाहरण को आदर्श वादिता के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। यह एक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति के लिए शोभनीय नहीं हैं। केजरीवाल स्वयं कहते थे कि वे राजनीति में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए आए हैं, लेकिन अब जब उन पर ही सवाल उठ रहे हैं, तब उनसे भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति की आशा करना बेमानी ही कही जाएगी। यहाँ सवाल यह भी उठ रहा है कि दिल्ली के शराब घोटाले में अभी तक जिन पर आरोप लग रहे हैं, उनको जमानत लेने का पर्याप्त आधार नहीं मिल रहा, इसका आशय यह भी है कि सरकार की ओर से कोई न कोई गलत आचरण किया गया होगा, अन्यथा एक मुख्यमंत्री को ऐसे ही गिरफ्तार नहीं किया जाता। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से भी यही कहा जा रहा है, उसके पास इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के संकेत पर पैसों का लेनदेन हुआ।

दिल्ली में शराब घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिस प्रकार से प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया है, उस पर विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष पर कई प्रकार के सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल उठाना विपक्ष की राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, लेकिन इन सवालों की परिधि में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उस पर विपक्ष कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। इससे इस बात को भी बल मिलता है कि दाल में कुछ काला अवश्य है। प्रवर्तन निदेशालय ने यह साफ तौर पर संकेत दिया है कि केजरीवाल शराब घोटाले का मुख्य आरोपी है। अब यह जांच के बाद ही पता चलेगा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लगाए जा रहे आरोप किस हद तक सही हैं या फिर केजरीवाल अपने आपको निर्दोष साबित कर पाते हैं या नहीं। अगर प्रवर्तन निदेशालय की ओर से लगाए गए आरोपी प्रमाणित होते हैं तो यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक संवैधानिक पद के प्रभाव का दुरुपयोग किया है।

हम यह भली भांति जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल अण्णा हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की उपज हैं। उस समय अरविंद केजरीवाल ने अपने आपको ऐसा प्रचारित किया कि एक वे ही भारतीय राजनीति के उच्चतम आदर्श हैं। लेकिन उनके आचरण पर स्वयं अण्णा हजारे ने सवाल उठाए थे, हालांकि अण्णा हजारे के सव. ालों को केजरीवाल ने दरकिनार कर दिया। इसका तात्पर्य यही है कि अन्ना हजारे राजनीति में जिस प्रकार का पारदर्शी व्यवहार चाहते थे, वैसा दिखाई नहीं दे रहा था। अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी समाजसेवी अण्णा हजारे की ओर से साफ सुथरी टिप्पणी आई है, जिसमें अण्णा हजारे ने शराब पर नीति बनाने से रोका था। अण्णा हजारे ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को उनके कर्मों का परिणाम बताया। आज दिल्ली का शराब घोटाला यही चरितार्थ करते हुए लग रहा है कि शराब किसी भी संस्था या व्यक्ति को बर्बाद कर देती है। यह बात केजरीवाल पर लागू होती है या नहीं, यह तो समय बताएगा, लेकिन जब आग लगती है तब ही धुंआ उठता है और इस धुंए का कालिमा किस किस के शक्ल को बिगाड़ने का काम करेगी, यह समय के गर्भ में है। केजरीवाल की सरकार पर सवाल उठना तो उसी समय प्रारंभ हो गए थे, जब उनका पहला मंत्री जेल में गया। उसके बाद तो जैसे लाइन ही लग गई। राजनीतिक शुचिता लाने का दम दिखाने वाले आम आदमी पार्टी के नेताओं पर इस प्रकार के आरोप लगने केवल राजनीतिक विद्वेष नहीं हो सकता। अगर यह कार्यवाही राजनीतिक होती तो स्वाभाविक रूप से इन सभी को जमानत भी मिल जाती। जमानत नहीं मिलने से यह आशंका प्रबल हो जाती है कि भ्रष्टाचार हुआ है। आम आदमी पार्टी के नेता भी केवल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का ही विरोध कर रहे हैं, कोई भी यह नहीं कह रहा कि दिल्ली में शराब घोटाला नहीं हुआ या फिर गोवा के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार का पैसा नहीं लगाया। यह बात सही है कि राजनीतिक तौर पर तर्क तो कई दिए जा सकते हैं, लेकिन इन तर्कों का आधार क्या है? यह कोई नहीं बता पाता। भारत की राजनीति में इसे विसंगति ही माना जाएगा कि कोई अपराधी और उसके समर्थक उसे ऐसे नायक के रूप में प्रस्तुत करते दिखाई देते हैं, जैसे वह समाज के लिए आदर्श बन गया हो। ऐसे तमाम उदाहरण दिए जा सकते हैं जिसमें नेता जमानत पर बाहर आकर राजनीतिक वातावरण को स्वच्छ करने की बात करते हैं। क्या वास्तव में ऐसे राजनेता देश के राजनीतिक वातावरण को सकारात्मक दिशा देने का सामर्थ्य रखते हैं। कदाचित नहीं। क्योंकि आज के राजनीतिक माहौल में राजनेता जैसा अपने आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, वैसा सिद्धांतत: होता नहीं है। उनके क्रियाकलाप केवल और केवल भ्रमित करने वाली राजनीति करने की ही होती है। देश में एक समय यह आम धारणा बन चुकी थी कि राजनीतिक भ्रष्टाचार इस देश की नियति बन चुकी है, लेकिन पिछले दस साल में इस धारणा को बदलने की सुगबुगाहट भी सुनाई देने लगी है। यह सुगबुगाहट कई राजनीतिक दलों को पसंद नहीं आ रही। ऐसे कई राजनेता हैं जो भ्रष्टाचार के दोषी सिद्ध हो चुके हैं और देश की राजनीति को सुधारने की कवायद कर रहे हैं। अब सवाल यह भी आता है कि क्या बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की बात करने का साहस दिखा सकते हैं। इसका उत्तर नहीं ही होगा, लेकिन वे फिर राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं। भारत में साफ सुथरी राजनीति के क्या यही मायने हैं? क्या ऐसे नेता राजनीति को सही दिशा दे सकते हैं, इसका उत्तर हमें स्वयं तलाश करना होगा? ऐसे ही दिल्ली सरकार के घोटाला में होता हुआ लग रहा है। क्योंकि यह स्पष्ट रूप से कहा जा रहा कि गोवा में 45 करोड़ रुपए हवाला के माध्यम से दिए गए। ऐसे में सवाल यही है कि क्या यही साफ सुथरी राजनीति के मायने हैं? तर्क कुछ भी हों, परन्तु अब ऐसी राजनीति से देश को अलग करने का समय आ गया है।

भारत में आर्थिक विकास के साथ-साथ आर्थिक असमानता भी

वित्तीय वर्ष 2023-24 की तृतीय तिमाही (अक्टोबर-दिसम्बर 2023) में भारत में आर्थिक विकास की दर 8.4 प्रतिशत रही है। कुछ विदेशी अर्थशास्त्री भारत की आर्थिक विकास दर को कमतर आंकते हुए दिखाई दे रहे हैं जबकि यह लगातार तिमाही दर तिमाही आगे बढ़ती ही जा रही है। अब तो विश्व की कई आर्थिक एवं वित्तीय संस्थानों ने भी वर्ष 2024 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर के सम्बंध में अपने अनुमानों को बेहतर किया है, परंतु अभी भी इन संस्थानों के यह अनुमान वास्तविक आर्थिक विकास दर की तुलना में बहुत कम हैं। दरअसल, विदेशी आर्थिक एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा विशेष रूप से भारत की आर्थिक विकास दर को आंके जाने के सम्बंध में उपयोग किए जा रहे मॉडल अब बोथरे साबित हो रहे हैं। हाल ही के समय में भारत के नागरिकों में "स्व" का भाव विकसित होने के चलते देश में धार्मिक पर्यटन बहुत तेज गति से बढ़ा है। उदाहरण के लिए अयोध्या धाम में प्रभु श्रीराम के भव्य मंदिर में श्रीराम लला के विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात प्रत्येक दिन औसतन 2 लाख से अधिक श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। यह तो केवल अयोध्या की कहानी है इसके साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर, उज्जैन में महाकाल लोक, जम्मू स्थित वैष्णो देवी मंदिर, उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री एवं यमनोत्री जैसे कई मंदिरों में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ रही है। भारत में धार्मिक पर्यटन में आई जबरदस्त तेजी के बदौलत रोजगार के लाखों नए अवसर निर्मित हो रहे हैं, जो देश के आर्थिक विकास को गति देने में सहायक हो रहे हैं। परंतु, यह तथ्य विदेशी आर्थिक एवं वित्तीय संस्थानों को दिखाई नहीं दे रहा है, जो कि केवल भारत की ही विशेषता है।

उक्त तथ्यों के अतिरिक्त अन्य कई कारक भी भारत की आर्थिक विकास दर को अब 9 से 10 प्रतिशत की सीमा में ले जाने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। आज भारतीय अर्थव्यवस्था की तुलना में भारत से आगे चल रही विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर में ठहराव आ गया है। जैसे अमेरिका एवं यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं आगे आने वाले समय में प्रतिवर्ष केवल 2 अथवा 3 प्रतिशत की दर से ही आगे बढ़ पाएंगी। इसी प्रकार चीन की अर्थव्यवस्था भी अब ढलान पर दिखाई दे रही है। जापान एवं जर्मनी की अर्थव्यवस्थाओं में तो आर्थिक मंदी देखी जा रही है। इस प्रकार विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत के अमृत काल में केवल भारतीय अर्थव्यवस्था ही तेज गति आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। वैसे भी भारत में अमृत काल तो अभी शुरू ही हुआ है एवं यह अगले 23 वर्षों अर्थात वर्ष 2047 तक यह खंडकाल जारी रहेगा। कुछ अर्थशास्त्री तो भारत के अमृत काल के बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था के इसी तरह तेज गति से आगे बढ़ते रहने की संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि भारत में वर्ष 1991-92 में प्रारम्भ किए आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्र के सुधार कार्यक्रम को अब 32 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, हालांकि वर्ष 1991-92 के बाद भी भारत में आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रों में सुधार कार्यक्रम लगातार जारी रहे हैं। अत: स्थिर हो चुके इन सुधार कार्यक्रमों के फल खाने का समय अब आ गया है।

भारत द्वारा वर्ष 1947 में राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, पिछले 77 वर्षों के दौरान भारत में लोकतंत्र लगातार मजबूत हुआ है एवं आज पूरे विश्व में भारत इस दृष्टि से प्रथम पायदान पर खड़ा है। भारत में लोकतंत्र के लगातार मजबूत होते जाने से विदेशी निवेशकों का भारत में विश्वास बढ़ा है जिसके चलते भारत में उद्योग जगत को पूंजी की कमी नहीं के बराबर रही है। पर्याप्त पूंजी की उपलब्धता के चलते भारत में आर्थिक विकास को गति ही मिली है। भारत में लगातार तेज हो रही आर्थिक विकास की दर के कारण भारत में बिलिनियर (100 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक की सम्पत्ति वाले नागरिक) की संख्या में सुधार हुआ है। पिछले वर्ष भारत में 94 नए बिलिनियर बने हैं। जबकि चीन में 115 बिलिनियर कम हुए हैं। विश्व में बिलिनियर की संख्या के मामले में भारत चीन एवं अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर आ गया है। भारत में आज 271 बिलिनियर हैं जबकि चीन में 814 एवं अमेरिका में 800 बिलिनियर हैं। मुंबई महानगर में तो अब 92 बिलिनियर निवास कर रहे हैं, जो चीन के बीजिंग महानगर के 91 बिलिनियर से अधिक है। इस प्रकार अब एशिया के किसी भी महानगर में सबसे अधिक बिलिनियर भारत के मुंबई महानगर में निवास कर रहे हैं। पूरे विश्व भारत के मुंबई महानगर से आगे अब केवल अमेरिका का न्यूयॉर्क महानगर (119 बिलिनियर) एवं ब्रिटेन का लंदन महानगर (97 बिलिनियर) ही है। वर्ष 2022-23 में चीन में बिलिनियर की संख्या घटी है। चीन में बिलिनियर की सम्पत्ति 15 प्रतिशत से कम हुई है। जबकि भारत में बिलिनियर की सम्पत्ति में वृद्धि दर्ज हुई है। यह भारत में तेज गति से हो रहे आर्थिक विकास दर के चलते सम्भव हो सका है। एक और कारक जो आगे आने वाले समय में भारत की आर्थिक विकास दर को लगातार उच्च स्तर पर बनाए रखने में सहायक हो सकता है वह है भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत आय का लगभग 2500 अमेरिकी डॉलर का होना है जो चीन में 13,000 से 14,000 अमेरिकी डॉलर के एवं दक्षिणी कोरीया में 32,000 से 33,000 अमेरिकी डॉलर के बीच की तुलना में बहुत कम है। इस दृष्टि से भारत को अभी बहुत आगे तक जाना है और यह केवल आर्थिक विकास की औसत दर को 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष के आसपास बनाए रखने से ही सम्भव होगा। इस प्रकार भारतीय नागरिकों में अपनी औसत आय को विकसित देशों की तुलना में बेहतर करने की अभी बहुत गुंजाइश है और यह भावना भारत की आर्थिक विकास दर को बढ़ाए रखने में सहायक होगी। दूसरे, भारत में तकनीकी क्षेत्र विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास की दर बहुत प्रभावकारी है, डिजिटल क्षेत्र में तो भारत आज पूरे विश्व को ही राह दिखाता नजर आ रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास के चलते भारत में विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिक. ों, व्यवसाइयों, प्रबंधकों, कृषकों आदि की उत्पादकता में भी सुधार दृष्टिगोचर है जो निश्चित ही भारत में आर्थिक विकास की गति को तेज करने में सहायक होगा।

आज अमेरिका एवं कनाडा में निवासरत एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्य कर रहे भारतीय मूल के नागरिक वापिस भारत आकर बसने के बारे में गम्भीरता से विचार कर रहे हैं क्योंकि अब अमेरिका एवं अन्य विकसित देशों की तुलना में भारत में लगातार तेज हो रही आर्थिक विकास की दर उन्हें आकर्षित कर रही है। उन्हें आज भारत में अधिक आय अर्जन के अतिरिक्त साधन उत्पन्न होते दिखाई दे रहे हैं।

एक सर्वे के अनुसार, लगभग 38,000 भारतीय जो अमेरिका में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्यरत हैं वे अब भारत वापिस आना चाहते हैं क्योंकि अमेरिका में कई कम्पनियां (गूगल, एमेजोन, माइक्रोसोफ्ट एवं मेटा सहित) अपने कर्मचारियों की छंटनी करती दिखाई दे रही हैं। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था तो स्पष्टत: आर्थिक मंदी की चपेट में आ चुकी है। जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था ने अक्टोबर-दिसम्बर 2023 की तिमाही में 8.4 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर हासिल की है। कई विदेशी वित्तीय संस्थानों ने वर्ष 2024 में भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान को आगे बढ़ा दिया है। अब तो भारत में, ग्रामीण इलाकों सहित, विभिन्न उत्पादों के खपत का स्तर भी लगातार बढ़ रहा है। केंद्र सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा विकास कार्यों के लिए अपने बजट में खर्च को लगातार बढ़ाया जा रहा है जिससे सामान्य नागरिकों के हाथों में अधिक पैसा पहुंच रहा है तथा इससे नागरिकों के बीच विभिन्न उत्पादों के खपत का स्तर बढ़ता दिखाई दे रहा है।

शहरी उपभोक्ता तो रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं के साथ साथ चार पहिया वाहन एवं मकान आदि खरीदने पर भी भारी मात्रा में पैसा खर्च कर रहे हैं। घरेलू खपत में बढ़ौतरी के साथ ही भारत से निर्यात में भी तेजी देखी जा रही है। फरवरी 2024 माह में निर्यात का स्तर पिछले 11 माह में सबसे अधिक रहा है। केंद्र सरकार का अनुमान है कि भारत वित्तीय वर्ष 2023-24 में निर्यात के क्षेत्र में अपने पिछले सारे रिकार्ड तोड़ देगा। मोर्गन स्टैनली के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर यह है कि भारत में निवेश : सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में एक बार फिर सुधार दिखाई दे रहा है। यह अनुपात आज 34 प्रतिशत तक पहुंच गया है और उम्मीद की जा रही है वित्तीय वर्ष 2027 तक यह बढ़कर 36 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। जिससे भारत की आर्थिक विकास दर को और अधिक बल मिलेगा।

हां, भारत में एक क्षेत्र अभी भी ऐसा है जिसके लिए चिंता होना स्वाभाविक है। वह क्षेत्र है आय की असमानता का। भारत की 10 प्रतिशत आबादी के पास देश की 77 प्रतिशत सम्पत्ति जमा हो गई है।

एक रिसर्च पेपर में यह बताया गया है कि भारत में आर्थिक विकास के साथ साथ आर्थिक असमानता भी बढ़ी है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत तक भारत की एक प्रतिशत आबादी की देश की कुल आय एवं सम्पत्ति में 22 .6 प्रतिशत एवं 40.1 प्रतिशत की भागीदारी रही है। आय की असमानता को देश में आर्थिक विकास को गति देकर ही दूर किया जा सकता है, जिसके लिए केंद्र सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भरसक प्रयास किए जा रहे हैं।

लोकसभा चुनाव-2024

ननद-भौजाई के बीच सियासी जंग

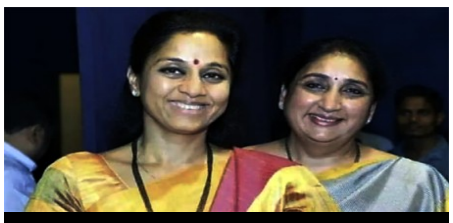

यहां राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने सुनेत्रा पवार को उम्मीदवार बनाया है

लोकसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने अपनी-अपनी रणनीति तैयार कर ली है और अब वे सियासी बिसात बिछाने में लग गए हैं। महाराष्ट्र में चुनावी जंग की तैयारी पूरी हो चुकी है। यहां सबसे रोचक जंग बारामती सीट पर होने वाली है। यहां राज्य के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने सुनेत्रा पवार को उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही इस सीट पर पवार परिवार के बीच चुनावी मकाबला देखने को मिलेगा। सुनेत्रा पवार, अजीत पबार की चचेरी बहन और शरद पबार की बेटी सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। इस संबंध में एनसीपी (अजीत गुट) के नेता सुनील तटकरे ने कहा कि यह लड़ाई पारिवारिक इगड़े के बजाय विचारधाराओं के टकराव का प्रतीक है। टिकट मिलने के बाद सुनेत्रा पवार ने एक मराठी न्यूज चौनल से कहा, मैं पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और महायुति (शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी) के सभी नेताओं को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने मुझे बारामती से उम्मीदवार बनाया। बारामती सीट को पवार परिवार का गढ़ माना जाता है। शरद पवार ने 1967 में पहली बार बारामती से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जीता था। इसके बाद उन्होंने 1972, 1978, 1980, 1985 और 1990 के विधान सभा चुनावों में भी इसी सीट से जीत हासिल की । इसके बाद में सुप्रिया सुले नें इस सीट पर चुनाव लड़ा और 2009 से इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रही हैं।

इस संबंध में एनसीपी (अजीत गुट) के नेता सुनील तटकरे ने कहा कि यह लड़ाई पारिवारिक इगड़े के बजाय विचारधाराओं के टकराव का प्रतीक है।

पूर्वांचल की राजनीति में समीकरण बनते बिगड़ते हैं

पूर्वांचल की राजनीति में जाति एक बड़ा फैक्टर है और यही से पूर्वांचल की राजनीतिक गणित उलझती है । हर पार्टियां सोशल इंजीनियरिंग का पासा बैठाने के बाद ही प्रत्याशी का चुनाव करती हैं। इस बार भी अब तक पासा ही बैठाया जा रहा। पक्ष विपक्ष सहित निर्दलीय तक पूर्वांचल में सिर्फ जातिगत गणित के भरोसे लड़ने को तरजीह दे रहें। पूर्वांचल में विकास का जो खाका खींचा जाना चाहिए था उससे अभी पूर्वांचल वैसे तो बहुत दूर है। पूर्वांचल की सियासी जमीन जातीय राजनीति के लिहाज से काफी मुफीद मानी जाती है। राजनीतिक पार्टियों का पूर्वांचल की सीटों पर काफी फोकस होता है। कहीं राजभर, कहीं भूमिहार, कहीं राजपूत तो किसी सीट पर मुसलमान और ब्राह्मण उम्मीदवारों को तरजीह मिलती है। एक उदाहरण के तौर पर भदोही लोकसभा को ही लें लीजिये जहाँ सर्वाधिक पांच बार पिछड़ी जाति तो चार बार ब्राह्मण, राजपूत व मुसलमान सांसद बने। भदोही लोकसभा सीट से सर्वाधिक पांच सांसद पिछड़ी जाति के रहें हैं। वहीं ब्राह्मण, राजपूत और मुसलमानों के बीच बराबरी का मुकाबला रहा है। 2009 के परिसीमन के बाद हुए तीन लोकसभा चुनावों में ब्राह्मण, राजपूत और पिछड़ी जाति के एक-एक सांसद हुए हैं। भदोही लोकसभा सीट 2009 के परिसीमन के पहले मिज. पुर-भदोही संसदीय सीट के नाम से जानी जाती थी। परिसीमन के बाद प्रयागराज की दो विधानसभा प्रतापपुर और हंडिया को जोड़ने के बाद भदोही लोकसभा अस्तित्व में आई। भदोही लोकसभा में ब्राह्मण, बिंद और मुसलमान मतदाता हार-जीत की भूमिका तय करते आ रहे हैं। अब तक के परिणामों की बात करें तो मुकाबला बराबरी वाला रहा है। इस लोकसभा से पांच बार पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों ने विजयश्री हासिल की है। वहीं ब्राह्मण, राजपूत एवं मुस्लिम सांसद भी चुने गए। भदोही सीट पर पिछड़ी जाति से आने वाले सांसदों में फूलन देवी, रामरति बिंद और रमेश चन्द्र बिंद और नरेंद्र कुशवाहा हैं। फूलन देवी ने यहां से दो बार जीत दर्ज की है। इस सरकार में मंत्री डॉ दयाशंकर मिश्र दयालु को भदोही का क्लस्टर इंचार्ज बनाया है ताकि भदोही के ब्राह्मण कोर वोटर भाजपा के किसी भी प्रत्याशी को स्वीकार कर लें क्यूंकि भदोही से लगे मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र में अपना दल एस और अनुप्रिया पटेल का काफी दबदबा है और वहां का दबदबा भदोही को भी प्रभावित करेगा। ऐसे में अपना दल के समर्थन के बाद भाजपा का प्रत्याशी यहाँ जातिय समीकरण से ही जीत हासिल कर पायेगा। अब देखना दिलचस्प होगा की ऐसे में भदोही समेत पूर्वांचल की तमाम सीटों पर जातिगत गणित की क्या स्थिति बनती है।

राजनीतिक पार्टियों का पूर्वांचल की सीटों पर काफी फोकस होता है। कहीं राजभर, कहीं भूमिहार, कहीं राजपूत तो किसी सीट पर मुसलमान और ब्राह्मण उम्मीदवारों को तरजीह मिलती है।

पंकज कुमार मिश्रा
जौनपुर यूपी

मजबूत प्रत्याशियों को अवसर देने के लिए कांग्रेस में मंथन

543 लोकसभा सीटों में से सबसे ज्यादा 80 सीटें यूपी में ही हैं। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। दरअसल, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों पर जिस पार्टी का कब्जा होता है. उसके लिए देश की सत्ता हासिल करना आसान हो जाता है। बीजेपी, सपा, बसपा और कांग्रेस ने तैयारी पूरी कर ली है। वहीं मजबूत प्रत्याशियों को मौका देने के लिए कांग्रेस भी लगातार मंथन कर रही है। ऐसे में इन दिनों राज बब्बर के नाम की चर्चा तेज है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी राज बब्बर को लोकसभा चुनाव में उतार सकती है। यही नहीं इसके लिए महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक की सीटों पर विचार चल रहा है। बता दे कि राज बब्बर 3 बार लोक सभा और दो बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। वहीं 2016 से 2019 तक यूपी काग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। इनके नाम पर चर्चा होने की दो बड़ी वजह मानी जा रही हैं, जिसमें पहली ये है कि इन्हें हाई कोर्ट की 2 साल के कारावास की सजा को निर्लंबित कर दिया गया है। वहीं दूसरी ये है कि कांग्रेस ने यूपी में पहले चरण के लिए उन्हें स्टार प्रचारक बनाया गया है। यही नहीं राज बब्बर काफी लंबे समय से पार्टी से जुड़े हैं । वर्तमान में राजनीतिक मामलों की समिति के सदस्य भी हैं। बीते 30 मार्च को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मतदान अधिकारी से मारपीट के वर्ष 1996 के एक मामले में दोषी करार दिए गाए। कांग्रेस नेता राज बब्बर को बड़ी राहत देते हुए दोष सिद्ध के आदेश को निर्लंबित कर दिया था। वहीं इसकी अगली सुनवाई 1 मई है। पार्टी उनके नाम पर गंभीरता से विचार कर रही है। गांधी परिवार से किसी के मैदान में न आने की स्थिति में वह रायबरेली से भी प्रत्याशी हो सकते हैं। वैसे महाराष्ट्र में भी एक सीट के लिए उनके, नाम पर विचार चल रहा है। राज बब्बर आगरा, फतेहपुर सीकरी और फिरोजाबाद से एक-एक लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि, 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें गाजियाबाद और 2019 के लोकसभा चुनाव में फतेहपुर सीकरी में पराजय का सामना करना पड़ा था। यूपी के आगरा में जन्मे अभिनेता राजबब्बर, यहीं पढ़े और फिर मायानगरी में चमके। साल था 1999 में सियासत का दौर कुछ और था। आगरा लोक सभा सीट पर भगवा परचम लहरा रहा था। भगवान शंकर रावत तीन बार के सांसद थे। लेकिन, राजबब्बर के ग्लैमर के चलते उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा ।

पहली बार राज बब्बर ने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़कर जीत हासिल की। उन्होंने साल 1999 में भाजपा सासद भगवान शंकर रावत को 1.12 लाख वोटों से हराया था। हालांकि, साल 2006 में सपा ने राजबब्बर को निलंबित कर दिया था। इसके बाद राजबब्बर ने फतेहपुर सीकरी का रुख किया। लेकिन, यहां उनका ग्लैमर, बसपा सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे रामवीर उपाध्याय की र्णनीति से मात खा गया था। रामवीर की पत्नी सीमा उपाध्याय फतेहपुर सीकरी से लोकसभा सांसद बनीं । इसके साथ राज बब्बर ने फिरोजाबाद सीट पर उपचुनाव में किस्मत आजमाया। 2009 उपचुनाव में फिरोजाबाद से सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की बह और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का मुकाबला कांग्रस के राजबब्बर से हुआ था, जहां डिंपल को राजबब्बर से शिकस्त मिली। इस तरह से राजबब्बर तीन बार लोकसभा सदस्य और दो बार राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं।

परदे के पीछे से अपराधी करते थे राजनेताओं की मदद

1989 के चुनाव के पूर्व भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण राजा मनकापुर आनन्द प्रताप सिंह को जीताने में सहयोग करते थे तो कर्नेलगंज में उमेश्वर प्रताप सिंह को बाद में वह स्वयं राजनीति में उतरकर पहले स्वयं, पत्नी व पुत्र ने राजनीति की कमान संभाली। गोरखपुर में स्व. हरिशंकर तिवारी डा. एस . एन.एम. त्रिपाठी व भृगुनाथ चतुवेर्दी के लिए तो विरेन्द्र प्रताप शाही कृष्णपाल सिंह एडवोकेट के लिए चुनाव की कमान संभाली तो उन लोगों को राजनैतिक संरक्षण की जरूरत पड़ती भी तो उनका समर्थन मांगना पड़ता था । बाद में यह सब एक मामूली बानगी है जो स्वयं राजनीति में कूद कर अपनी पैरवी खुद करने के लिए मान्यवर हो गये ।

आज तक किसी भी सरकार ने इस समिति की या 70 के दशक में बने राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों को लागू करने में कोई रुचि नहीं दिखाई। ऐसी तमाम सिफा. रिशें आज तक धूल खा रही हैं। ऐसा नहीं है कि सत्ता और अपराध का गठजोड़ आज की घटना हो। मध्य युग के सामंतवादी दौर में भी अनेक राजाओं का अपराधियों से गठजोड़ रहता था। यह तो प्रकृति का नियम है कि अगर समाज में ज्यादातर लोग सतोगुणी या रजोगुणी हों तो भी कुछ फीसद लोग तो तमोगुणी होते हीं हैं। ऐसा हर काल में होता आया है।

फिर भी सतोगुणी और रजोगुणी प्रवृत्ति के लोगों का प्रयास रहता है कि समाज की शांति भंग करने वाले या आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को निर्यंत्रित किया जाए, उन्हें रोका जाए और सजा दी जाए। यह सब होने के बावजूद समाज में अपराध होते हैं। क्योंकि आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को अपराध करना कतई अनुचित नहीं लगता। उसके लिए तो अपराध सहज प्रक्रिया ही होती है। योगी आदित्यनाथ अगर यह दावा करें कि उनके शासन में उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो गया तो क्या कोई इस पर विश्वास करेगा? जबकि आए दिन महिलाएं उत्तर प्रदेश में हिंसा और बलात्कार की शिकार हो रही हैं। पुलिस वाले होटल में घुस कर बेकसूर व्यापारियों कीहत्या कर रहे हैं, और थानों में पीड़ितों की कोई सुनवाई नहीं होती। हां, यह जरूर है कि सड़कों पर जो छिछोरी हरकते होती थीं, उन पर योगी सरकार में रोक जरूर लगी है। पर फिर भी अपराधों का ग्राफ कम नहीं हआ।

90 के दशक में आई वोरा समिति की रिपोर्ट अपराधियों के राजनेताओ, अफसरों और न्यायपालिका के साथ गठजोड़ का खुलासा कर चुकी हैं, और इस परिस्थिति से निपटने के सुझाव भी दे चुकी है। अगर कोई यह कहे कि योगी आदित्यनाथ की सरकार साम दाम, दंड, भेद अपना कर उत्तर प्रदेश से एक एक करके सभी माफिया का सफाया करवा रही है, या ऐसे हालात पैदा कर रही है कि ये माफिया एक एक करके मौत के घाट उतर रहे हैं, तो यह अर्धसत्य होगा। क्योंकि आज देश का कोई भी राजनैतिक दल ऐसा नहीं है जिसमें गुंडे, मवालियों, बलात्कारियों और माफिया को संरक्षण न मिलता हो। फर्क सिर्फ इतना है कि जिसकी सत्ता होती है वो केवल विपक्षी दलों के माफिया को निशाने पर रखता है। अपने दल के अपराधियों की तरफ से आंख मूंद लेता है। यह सिलसिला पिछले पैंतीस बरसों से चला आ रहा है। आजादी के बाद से 1990 तक अपराधी, राजनेता नहीं बनते थे। क्योंकि हर दल अपनी छवि न बिगड़े, इसकी चिंता करता था। पर ऐसा नहीं था कि अपराधियों को राजनैतिक संरक्षण प्राप्त न रहा हो। चुनाव जीतने, बूथ लूटने और प्रतिद्वंद्वियों को निपटाने में तब भी राजनेता पर्दे के पीछे से अपराधियों से मदद लेते थे और उन्हें संरक्षण प्रदान करते थे। 90 के दशक से परिस्थतियां बदल गईं।

साहित्यिक लेखन अपने स्वाभिमान और उच्च जीवन मूल्यों से कभी समझौता नहीं किया माखनलाल चतुर्वेदी ने

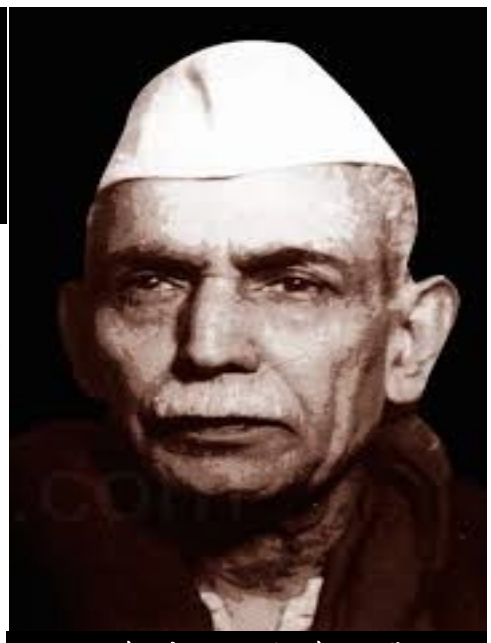

उस दौर के राष्ट्वादी और निर्भीक पत्र-पत्रिकाओंको अग्रेजी हुकूमत के बार-बार दमन, तथाकथित कानून, मुचलकों, जुब्ती, जमानतों कासामना करना पड़ा। पत्रकारिता करते हुए माखनलाल चतुवेदी को भी इन सब परिस्थितियोंका सामना करना पड़ा। बावजूद इसक वे अग्रेज हुंकूमत के आगे कभी नहीं झुके। उनकी लेखनी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हमेशा आग उगलती रही।

सदी के पूर्वार्द्ध में अनेक महमपुरुषों ने राष्ट्रीय परिदृश्य पर अपने बहुआयामी व्यक्तित्व और कालजयी कृतत्व की छप छोड़ी । ऐसे ही महापुरुषों में दादा माखनलाल चतुर्वेदी का नाम बड़े ही सम्मान और गौरव के साथ लिया जाता है। वे सुधीचिंतक, कवि और प्रखर पत्रकार होने के साथ- साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनापतियोंमें से एक थे। महात्मा गांधी से प्रेरित होकर एक बार जो उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का निश्चय किया, तो उस निश्चय पर जीवन भर अटल रहे। कोई भी लालच और प्रलोभन उनके विश्वास को खंडित नहीं कर पाया। साहित्यकार के रूप में भी माखनलाल चतुर्वेदी की अधि कांश कविताएं देश प्रेम पर केन्द्रित हैं। 'प्रभा' और 'कर्मवीर' जैसे प्रसिद्ध पत्रों के संपादक के तौर पर उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जोरदार प्रचार किया और नई पीढ़ी का आह्वान किया कि वह गुलामी की जंजीरों को तोड़ कर बाहर निकलें। इसके लिये उन्हें कई बार ब्रिटिश साम्राज्य का कोपभाजन बनना पड़ा।

माखनलाल चतुर्वेदी सच्चे देशभक्त थे। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आदि सभी आंदालनों में उन्होंने हिस्सेदारी की और जब इसके लिए गिरफ्तारी देने का मौका आया, तो वे इससेजूरा सा भी पीछे नहीं हटे। समाचार पत्र 'हिन्दी केसरी' ने साल 1908 में श्राष्ट्रिय आंदोलनऔर बहिष्कारश विषय पर एक निबंध प्रतियोगिता का अयोजन किया। प्रतियोगिता मेंनौजवान माखनलाल चतुरवेदी भी शामिल हुए और उनका निबंध अव्वल नंबर पर आया। अखबार के यशस्वी संपादक माधवराव सप्रे को माखनलाल चतुर्वेदी की लेखनी में अपारसंभावनाओं से युक्त पत्रकार-साहित्यकार के दर्शन हुए। सप्र ने चतुर्वेदी को इस दिशा मेंऔर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। माखनलाल चतुर्वेदी नियमित लिखने लगे। कविताओं केसाथ-साथ उन्होंने पत्रकारिता भी शुरू कर दी। वह दिन भी आया, जब वे अपनी अध्यापककी नौकरी छोड़कर पूरी तरह से पत्रकारिता, साहित्य और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए सम. र्पितहो गए। खंडवा के हिन्दीप्रेमी कालूराम गंगराड़े एक मासिक पत्रिका निकालना चाहते थेऔर इसके लिए उन्हें योग्य संपादक की तलाश थी। उनकी तलाश माखनलाल चतुवेदीपर जाकर खत्म हुई। अप्रैल, 1913 में श्प्रभाश का प्रकाशन आरंभ हुआ, जिसके संपादनकी ज़िम्मेदारी माखनलाल चतुवेदी ने संभाली। उनके संपादन में इस पत्रिका के कईमहत्वपूर्ण अंक निकले, जिनकी चर्चा पूरे देश में हुई। 'प्रभा' के सम्पादन काल के दौरान ही माखनलाल चतुर्वेदी का परिचय एक और महान देशभक्त एवं पत्रकार गुणेश शंकर विद्यार्थी से हआ, जिनके देश-प्रेम और लेखन से वे बहुत प्रभावित हुए। माखनलाल चतुर्वेदी ने आगे चलकर साल 1919 में जबलपर से समाचार पत्र कर्मवीर का प्रकाशन शुरू किया। इस अखबार के लेख बड़े तेवर वाले होते थे। अखबार का स्वरूप और उसकेविषय के चलेते 'कर्मवीर' जल्दी ही लोगों में बेहद लोकप्रिय हो गया। अखबार की लोकप्रियता अंग्रेजी हुकूमत से देखी नहीं गई और 12 मई, 1921 को माखनलाल चतुर्वेदीको राजद्रोह के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। वे एक साल तक जेल में रहे। साल 1922 में उन्हें कारागार से रिहाई मिली। जेल से रिहाई के बाद वे फिर पत्रकारिता में लगगए। जेल का कारावास भी उनका हौसला नहीं तोड़ पाया। इस दौरान प्रतापश के सम्पादकगणेश शंकर विद्यार्थी पर अग्रेज हकुमत की गाज गिरी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।गणेश शंकर विद्यार्थी की गिरफ्तारी के बाद 'प्रताप' का सम्पादकीय कार्य-भार संभालने की जिम्मेदारी माखनलाल चतुर्वेदी को मिली। परतंत्र भारत में पत्रकारिता सास्कृतिकजागरण, राजनीतिक चेतना, साहित्यिक सरोकार, और दमन का प्रतिकार इन चार पहियोंके रथ पर सवार थी। यही वजह रही कि उस दौर के राष्ट्वादी और निर्भीक पत्र-पत्रिकाओंको अग्रेजी हुकूमत के बार-बार दमन, तथाकथित कानून, मुचलकों, जुब्ती, जमानतों कासामना करना पड़ा। पत्रकारिता करते हुए माखनलाल चतुवेदी को भी इन सब परिस्थितियोंका सामना करना पड़ा। बावजूद इसक वे अग्रेज हुंकूमत के आगे कभी नहीं झुके। उनकी लेखनी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हमेशा आग उगलती रही।

साहित्यिक अवदान में उन्होंने कविताएँ, निबंधि, नाटक और कहानियां भी लिखीं। उनके अभिभाषण और व्याख्यानों मेंभी उनकी राष्वादी सोच परिलक्षित होती है। 4 अप्रैल, 1925 को जब खंडवा से माखनलालचतुर्वेदी ने ष्कर्मवीरश का पुनः प्रकाशन किया तब उनका देशवासियों से आह्वान था,श्आइए, गरीब और अमीर, किसान और मजदूर, उच्च और नीच, जित और पराजित के भेदों को ठुकराइए। प्रदेश में राष्ट्रीय ज्वाला जगाइए और देश तथा संसार के सामने अपनी संतानें स्वतंत्र भारत शक्तियों को ऐसा प्रमाणित कीजिए, जिसका आने वाली के रूप में गर्व करें।' पत्रकारिता और अखबारों के संपादन के साथ-साथ माखनलाल चतर्वेदी अनवरतसाहित्य साधना करते रहे। झसमें कहीं कोई रुकावट नहीं आई। 'हिममकिरीटिनीं, तरंगिणी', 'युग चरण', समर्पणं, मरण ज्वार, 'माता', 'वेणु लो गूंजे धरा',श्बीजुरीकाजल आँज रहीश आदि माखनलाल चतबवंदी की प्रसिद्ध काव्य कुतियाँ हैं। वहीं 'कृष्णार्जुन युद्ध' साहित्य के देवताश, ष्समय के पांवश, ष्अमीर इरादे-गरीब इरादेश आदि उनकी प्रमुख गद्यात्मक कृतियों हैं। हिन्दी साहित्य में माखनलाल चत्वेंदी के उच्च कोटि के योगदान कोदेखते हुए उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान से सम्मानित किया गया। साल 1943 में काव्यसंग्रह हिम किरीटिनीश पर उन्हें देव परस्कार मिला, जो उस समय का हिन्दी साहित्य कासवस बड़ा पुरस्कार था। साल 1955 में साहित्य अकादमी ने माखनलाल चतुर्वदों कोकाव्य संग्रह शहिमतरंगिणीश के लिये साहित्य अकादमी प्रस्कार से सम्मानित किया। पुष्पकी अभिलाषा और 'अमर राष्ट्र' जैसी ओजस्वी रचनाओं के रचयिता महाकवि माखनलालचतुर्वेदी के कृतित्व को सागर विश्वविद्यालय ने साल 1959 में डी. लिट् की मानद उपाधि से विभूषित किया। साल 1963 में भारत सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम, पत्रकारिता औरसाहित्य में माखनलाल चतुवंदी के अमूल्य योगदान को सराहते हुए, उन्हें पद्भूषण सम्मान से अलंकृत किया। माखनलाल चतुर्वेदी के साहित्यिक अवदान का एक परिचय उर्दू के नामवर हस्ताक्षर रघुपति सहाय यानी फिराक गोरखपुरी की इस टिप्पणी से मिलता है, उनके लेखों को पढ़ते समय ऐसा मालूम होता था कि आदि शक्ति शब्दों के रूप में अवतरित हो रही है या गंगा स्वर्ग से उतर रही है। यह शैली हिन्दी में ही नहीं, भारत की दूसरी भाषाओंमें भी विरले ही लोगों को नसीब हुई । मुझ जैसे हजारों लोगों ने अपनी भाषा और लिखने की कला माखनलाल जी से ही सीखी। माखनलाल चतुर्वेद ने अपनी जिंदगी में चाहे पत्रकारिता की हो या फिर साहित्यिक लेखन अपने स्वाभिमान और उच्च जीवन मूल्यों से कभी समझौता नहीं किया। देश में स्वराज्य आये, यह उनके जीवन और लेखन कामुख्य ध्येय था। खुद तो इस राह पर चले ही, बल्कि दूसरे साहित्यकारों को भी दपेलिए प्रेरित किया। मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन में माखनलालचतुर्वेदी ने बाकायदा यह प्रस्ताव पारित कराया था, साहित्यकार स्वराज्य प्राप्त करने केध्येय से लिखें। वहीं साहित्य के संदर्भ में उनको स्पष्ट अवधारणा थी, लोग साहित्यको जीवन से भिन्न मानते हैं, वे कहते हैं साहित्य अपने ही लिए हो। साहित्य का यह धंधा नहीं कि हमेशा मधुर ध्वनि ही निकाला कर जीवन को हम एक रामायण मान लें। रामायण जीवन के प्रारंभ का मनोरम बालकांड ही नहीं, किंतु करुण रस में ओतप्रोत अरण्यकांड भी है और धध कती हुई युद्धाग्नि से प्रज्वलित लंकाकांड भी है।

उन्नतियों के बावजूद कुरीतियों का शिकार होती बेटियाँ

एक लड़की समाज के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। वह एक मा, एक बेटी, एक पत्नी इस तरह कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती है। उसे घर की शांति बनाए रखने वाली स्तंभ माना जाता है और फिर भी उसका अपमान किया जाता है। स्त्रियां ही संतति की परम्परा में मुख्य भूमिका निभाती है फिर भी प्राचीन समाज से लेकर आधुनिक कहे जाने वाले समाज तक स्त्रियां उपेक्षित ही रही है।

आज प्रत्येक क्षेत्र में बालिकाओं अनेक उन्नतियों के बावजूद भी वह अनेक कुरीतियों की शिकार होकर जीवन जीने के लिए विवश हैं। यह कुरीतियां बेटियों के आगे बढने में बाधाएं उत्पन्न करती है। पढ़े-लिखे लोग और जागरूक समाज भी इस समस्या से अछूता नहीं है। देश में आज भी प्रतिवर्ष लाखों लड़कियों को जन्म लेने से पहले ही कोख में मार दिया जाता है। आज भी समाज के अनेक घरों में बेटा, बेटी में भेद किया जाता है। बेटियों को बेटों की तरह अच्छा खाना और अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती है। समाज में आज भी बेटियो को बोझ समझा जाता है।

हमारे देश में यह एक बड़ी विडंबना है कि हम बालिका का पूजन तो करते हैं। लेकिन जब हमारे खुद के घर बालिका जन्म लेती है तो हम दु:खी हो जाते हैं। देश में सभी जगह ऐसा देखा जा सकता है। देश के कई प्रदेशों में तो बालिकाओं के जन्म को अभिशाप तक माना जाता है। लेकिन बालिकाओं को अभिशाप मानने वाले लोग यह क्यों भूल जाते हैं कि वह उस देश के नागरिक हैं जहां रानी लक्ष्मीबाई जैसी विरांगनाओं ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। हमारे यहां आज भी बेटी पैदा होते ही उसकी परवरिश से ज्यादा उसकी शादी की चिन्ता होने लगती है।

आज महंगी होती शादियों के कारण बेटी का बाप हर समय इस बात को लेकर चिंतित नजर आता है कि उसकी बेटी की शादी की व्यवस्था कैसे होगी। समाज में व्याप्त इसी सोच के चलते कन्या भ्रूण हत्या पर रोक नहीं लग पायी है। कोख में कन्याओ को मार देने के कारण समाज में आज लड़कियों की काफी कमी होने से लिंगानुपात गड़बड़ा गया है। पिछले कुछ वर्षों में देश में जन्म के समय लिंगानुपात में बढ़ोतरी होना शुभ संकेत हैं। संसद में एक सवाल का जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्री ने बताया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने बालिकाओं के अधिकारों को स्वीकार करने के लिए जनता की मानसिकता को बदलने की दिशा में सामूहिक चेतना जगाई है।

इस योजना ने भारत में सीएसआर (बाल लिंग अन. पात) में गिरावट के मुद्दे पर चिंता जताई है। यह राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) में 15 अंकों के सुधार के रूप में परिलक्षित होता है। जो कि 2014 में 918 था। जबकि 2022-23 में 15 अंक बढ़कर 933 हो गया। अगर समाज में बेटियों को उचित शिक्षा और सम्मान मिले तो बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नही रहेगी। इसलिए यदि यह कहा जाय की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना नही हम सबकी एक जिम्मेदारी है तो इसमें कुछ गलत नही है। यदि हम सभी एक अच्छे समाज का निर्माण करना चाहते है तो हम सबका यही फर्ज बनता है हम इन बेटियों को भी भयमुक्त वातावरण में पढ़ाये। उन्हें इतना सशक्त बनाये की खुद गर्व से कह सके की देखो वह हमारी बेटी है जो इतना बड़ा काम कर रही है।

भारत में प्रतिवर्ष तीन से सात लाख कन्या भ्रूण नष्ट कर दिए जाते हैं, इसलिए यहां महिलाओं से पुरुषों की संख्या 5 करोड़ ज्यादा है। समाज में निरंतर परिवर्तन और कार्य बल में महिलाओं की बढ़ती भूमिका के बावजूद रूढिवादी विचारधारा के लोग मानते हैं कि बेटा बुढ़ापे का सहारा होगा और बेटी हुई तो वह अपने घर चली जाएगी। बेटा अगर मुखाग्नि नहीं देगा तो कर्मकांड पूरा नहीं होगा। लड़कियों ने अपने काम और समर्पण के बल पर कई क्षेत्रों और क्षेत्रों में खुद को साबित किया है। वे अधिक प्रतिभाशाली, आज्ञाकारी, मेहनती और परिवार और अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। लड़कियाँ अपने परिवार और माता-पिता के प्रति अधिक देखभाल करने वाली और प्यार करने वाली होती हैं और वे हर काम में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देती हैं।

देश की अर्थव्यवस्था में भी महिलाओं का अहम योगदान है। वे श्रम शक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और व्यवसायों की वृद्धि और विकास में योगदान देती हैं। एक तरफ जहां बेटी को जन्मते ही मरने के लिये लावारिश छोड़ दिया जाता है। वहीं झुंझुनू जिले की मोहना सिंह जैसी बालिकायें भी है जो आज देश में फाईटर प्लेन उड़ा कर पूरे देश में जिले का मान बढ़ा रही हैं। समाज में सभी को मिलकर लडका-लडकी में भेद नहीं करने व समाज के लोगों को लिंग समानता के बारे में जागरूक करने की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। देश में बालिकाओं के साथ आए दिन बलात्कार, प्रताडना की घटनाएं अखबारों की सुर्खिया बनती हैं। बालिकायें कही भी अपने को सुरक्षित नहीं समझती हैं। चाहे घर हो या स्कूल अथवा कार्य स्थल। हर जगह वहशी भेडिये उन पर नजरे गड़ायें रहते हैं। उन्हे जब भी मौका मिलता है नोंच डालते हैं। ऐसे माहौल में देश की बालिकायें कैसे आगे बढ़ पाएंगी

समाज के पढ़े लिखे लोगों को आगे आकर कन्या भ्रूण हत्या जैसे घिनोने कार्य को रोकने का माहौल बनाना होगा। ऐसा करने वाले लोगों को समझा कर उनकी सोच में बदलाव लाना होगा। लोगों को इस बात का संकल्प लेना होगा कि ना तो गर्भ में कन्या की हत्या करेगें ना ही किसी को करने देगें। तभी देश में कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लग पाना संभव हो पायेगा।

सरकार व समाज को मिलकर ऐसे वातावरण का निर्माण करने का प्रयास करना चाहिये जिसमें बालिकायें खुद को महफूज समझ सकें। बालिकाओं पर अत्याचार करने वालों के मन में भय व्याप्त करने के लिये सरकार को कानून में और अधिक सुधार करना चाहिये। बालिकाओं को कई प्रकार के भेदभाव का शिकार होना पड़ता है।

समाज और राष्ट्र के विकास के लिए बालिकाओं के महत्व को स्वीकार करना और बढ़ावा देना आवश्यक है। शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है। एक शिक्षित लड़की ही अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के आर्थिक विकास में योगदान दे सकती है। कानूनी सुरक्षा बालिकाओं के अधिकारों की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जागरूकता कार्यक्रमों और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से लड़कियों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने के लिए भी उतना ही आवश्यक है।

हमारे समाज का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज अपनी बच्चियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और उन्हें कितना महत्व देते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कानूनी सुरक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से बालिकाओं को सशक्त बनाना न केवल एक नैतिक दायित्व है बल्कि सामाजिक विकास के लिए एक जरूरी आवश्यकता भी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि लड़कियों को आगे बढ़ने, सीखने के समान अवसर मिले। तभी हम एक संतुलित, न्यायसंगत और समृद्ध समाज बना सकेगें।

लोकसभा चुनाव-2024

आगामी लोकसभा चुनाव में असम के राजनीतिक परिदृश्य से कांग्रेस का सफाया तयःवियूरामवाहगे

अरुणाचल प्रदेश के मख्यमंत्री पेमाखांडू और चार अन्य भाजपा उम्मीदवारों का निर्विरोध विधायक चुना जाना तय है क्योंकि बुधवार को पर्चा दाखिल करने के आखिरी दिन किसी अन्य उम्मीदवार ने उनकी विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल नहीं किया। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ होंगे। 60 सदस्यीय विधानसभा और दो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों (अरुणाचल पश्चिम औरअरुणाचल पूर्व) के लिए मतदान 19 अपैल को होगा। इसके अतिरिक्त केंद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू ने मंगलवार को अरुणाचल पश्चिम लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। चुनाव अधिकारियों ने बताया कि रीजीजू ने पश्चिमी सियांग जिले के मुख्यालय आलो में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष वियूरामवाहगे ने कहा है कि उनके दल को भरोसा है कि वह आगामी चुनावों में राज्य के राजनीतिक परिदृश्य से कांग्रेस का सफया कर देगा। उन्होंने एक साक्षात्कार के दौरान बताया कि 19 अप्रैल को राज्यकी दो लोकसभा और 60 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में ऐसा माहौल बना हुआ है किदेश की सबसे पुरानी पार्टी को अपमानजनक हार का सामना करना पड़ेगा। असम-असम में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत पांच लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए गुरुवार को अधिसूचना जारी की गई।

एक निर्वाचन अधिकारी ने यह जानकारी दी। दूसरे चरण में नागांव, दरांग उदलग. रीप दीफू (अजजा)एसिलचर (अजा) और करीमगंज में मतदान होगा। इसके अतिरिक्त लोकप्रिय गायक जुबीन गर्ग ने कहा कि असम केलोग नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) को कभी स्वीकार नहीं करेंगे और बिना हिंसा के इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह विभिन्न मंचों पर सीएए के खिलाफ विरोध जारी रखेंगे। उन्होंने इस अधिनियम को रद्द करने की खातिर कानूनी लड़ाई जीतने के लिए ठोस कदम उठाने का भरी आहानकिया। सोशल मीडिया मंच ष्फेसबुकष पर अपने पोस्ट मेंगर्ग ने कहा कि 2017 में जब यह विधेयक आया था वहतभी से इसंका विरोध कर रहे हैं और वह अपने रुख परकायम हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम केडिबरूगढध संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)उम्मीदवार के रूप में पिछले मंगलवार को अपना नामांकन दाखिल किया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा के साथ सोनोवाल ने चुनाव अधिकारी बिक्रम कैरी के समक्ष अपना नामांकन पत्रदाखिल किया। **मणिपुर**-आईटीएलएफ ने कुकी. जो समुदाय के सदस्यों से बाहरी मणिपुर लोकसभा सीट परचुनाव नहीं लड़ने को कहा है। हालांकिए संगढन ने एकबयान में समुदाय के सदस्यों से लोकसभा चुनाव मेंमतदान करने को कहा है । इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फेरम(आईटीएलएफे ने सोमवार को जारी बयान में कहा, हमअपने समृदाय के सदस्यों को सलाह देते हैं कि वे आगाम. ोलौकसभा चुनाव में मतदान करके अपने अधिकार काप्रयोग करेंए लेकिन बाहरी मणिपुर सीट पर चुबजाव लड़ने से दूर रहें । बयान में कहा गया कि घटक जनजातियों के साथ परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पाटी (भाजपा) ने मंगलवार को इनर मणिपुर लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्रीराजकुमार रजन सिंह का टिकट काटकर प्रदेश के शि क्षा मंत्री टी. बसंतकुमार सिंह को इस सीट से उम्मीदवारबनाया है। टी. बसंतकुमार (59) पूर्व केंद्रीय मंत्री टी. चाओबासिंह के बेटे हैं। भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के पूर्व अधिकारी बसंतकुमार अभी विश्युपुर जिले में नामबोलविध नसभा सीट से विधायक हैं। कांग्रेस ने आगामी चुनावोंके सीट सजएनयू जिवाहरलाल नेहर विश्वविद्यालय) के प्रफिसरअंगोमचा दिमोल अकोइजाम और बाहरी मणिपूर लोकसभा सीट से पूर्व विधायक अल्फ्रेह कत्रणम आर्थर को टिकट दिया है।

एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है । **मिजोरम**-मिजोरम कीएकमात्र लोकसभा सीट से भारतीयजनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार वनलाल. हमुअका ने सोमवार को राज्य केलोगों से भाजपा के बारे में अपनी धारणा बदलने को कहा। भाजपा की मिजोरम इकाई के अध्यक्ष वनलालहमुअका ने कहाकि मिजोरम को भी अधिक विकास के लिए अन्य पूर्वोत्तर राज्यों की तरह केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग)सरकार के साथ सहयोग करने के तरीके सीखने चाहिए। मिजोरम की सत्तारूढ़ पार्टी जोरम पीपूल्समुवमेंट,(जेडपीएम) आणामी लोकसभा चुनाव के लिएएक अप्रैल से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करेगी।जेडपीएम के एक वरिष्ठ नेता ने सोमवार को यह जानकारीदी। मिजोरकम की एकमात्र लोकसभा सीट के लिए मतदान9 अप्रेल को होणा। भाजपा ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह मेघालय में लोकसभा की दोनों सीटों पर सत्तारूढ़ नेशनल पीपूल्स पार्टी(एनपीपी)और मणिपुर की दो संसदीय सीटों में से एक पर नगाप्रीपल्स फ्रट(एनपीएफे को समर्यन देगी । केंद्र की सत्तारूढपार्टी बे नगालैंड की एकमात्र लकसभा सीट पर राज्य कीसतारूढ़ नेशनलिस्ट डेमाक्रटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनहीपीपी) का भी समर्थन करने की घोषणा की।

फर्जी नारीवाद और नग्नता से दूर अच्छी फिल्म 'क्रू'

महिला सशक्तिकरण के नाम पर यह फिल्म पिछली फिल्म जैसी नहीं है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि रिया कपूर फिल्म का निर्देशन करने के बजाय सिर्फ निर्माण पर ही अड़ी रहीं। क्रू आसान और मनोरंजक फिल्म है।

तब्बू, कृति सेनन और करीना कपूर खान की महिला केंद्रित फिल्म क्रू गत दिनों सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म विजय माल्या और किंगफिशर एयरलाइंस की पृष्ठभूमि पर आधारित है। विजय वालिया नाम की सास्वता चटर्जी कोहिनूर एयरलाइंस के मालिक की भूमिका निभाती हैं, जहां गीता सेठी (तब्बू), जैस्मीन (करीना कपूर खान) और दिव्या (कृति सेनन) केबिन क्रू के रूप में काम करती हैं। दो घंटे चार मिनट की इस फिल्म में कॉमेडी, सस्पेंस, डकैती और बहुत सारा ग्लैमर है। 'वीरे दी वेडिंग' के निर्माताओं की ओर से आने वाली 'क्रू' में बनावटी नारीवाद, नग्नता और 'फोर मोर शॉट्स प्लीज' वाली भावना नहीं है। शुक्र है कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर यह फिल्म पिछली फिल्म जैसी नहीं है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि रिया कपूर फिल्म का निर्देशन करने के बजाय सिर्फ निर्माण पर ही अड़ी रहीं। क्रू आसान और मनोरंजक फिल्म है। कृति भले ही तब्बू और करीना पर थोड़ी कम रहीं हों, लेकिन जब आप इतने टैलेंट के साथ स्क्रीन शेयर करते हैं तो कोई शिकायत नहीं कर सकता।

कहानी

करीना, कृति और तब्बू स्टारर क्रू दो टाइमलाइन में चलती है। एक, जहां तीनों से पूछताछ हो रही है और दूसरा (पिछला संस्करण), जहां आपको उनकी कहानी के साथ-साथ उनकी दोस्ती की गहराई के बारे में भी पता चलता है। तब्बू इस केबिन क्रू में सबसे वरिष्ठ सदस्य की भूमिका निभाती हैं, दूसरे नंबर पर करीना और फिर कृति हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि एक एयरलाइन दिवालिया हो जाती है और उसके कर्मचारियों को परेशानी झेलने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

कृति, तब्बू और करीना की एक छोटी पृष्ठभूमि कहानी भी प्रदर्शित की गई है जहां निर्माता आगामी डकैती के लिए मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास करते हैं। फिल्म में तब दिलचस्प मोड़ आता है जब तीनों कलाकारों को अपने दुख के बीच ढेर सारा सोना मिलता है। इसके साथ, दिलजीत दोसांझ का एक छोटा लेकिन प्यारा परिचय दिया गया है, जो कृति सेनन की प्रेमिका की भूमिका निभा रहे हैं। यह महसूस करने के बाद कि कंपनी वास्तव में दिवालिया हो गई है, वादे झूठे हैं और उसका पीएफ निर्विवाद है, तब्बू उर्फ गीता अन्य दो को जोखिम उठाने के लिए प्रेरित करती है। मौज-मस्ती और विलासिता के कुछ पल बिताने के बाद, उनका अच्छा समय कम हो जाता है और तीनों से पूछताछ होनी शुरू हो जाती है। आपस की लड़ाई, भीतर की लड़ाई और सिस्टम से लड़ाई ये महिलाएं तय करती हैं। कॉमेडी-ड्रामा की शैली के तहत सब कुछ रखते हुए, निर्माता हर तरह सही डोर खींचने में सक्षम हैं।

क्रू का निर्देशन राजेश ए कृष्णन द्वारा किया गया है, जिन्हें लॉकडाउन ओटीटी रिलीज, लूटकेस के लिए जाना जाता है। कृष्णन ने कुणाल खेमू अभिनीत फिल्म से मौके का पूरा फायदा उठाया था, हालांकि क्रू पीछे रह गई। इस फिल्म को अतार्किक न लगने देने के लिहाज से कृष्णन ने इसमें कई खामियां उजागर कर दी हैं। फिल्म निर्माता की एक और सबसे बड़ी गलती दिलजीत और कपिल शर्मा को कॉमेडी फिल्म में कास्ट करना है लेकिन उनकी कॉमिक टाइमिंग का उपयोग नहीं करना है। दोनों लगभग गंभीर भूमिका में आ गए हैं और उन्हें सबसे हरे झंडे के रूप में शसिर्फश प्रस्तुत किया गया है। परिस्थितियों को देखते हुए निर्देशक और लेखक आसानी से अपनी पंचलाइन पेश कर सकते थे। हालाँकि, महिला सशक्तीकरण के नाम पर विचित्र बातें न करने के लिए कृष्णन की सराहना की जानी चाहिए। उन्होंने फिल्म को कई मायनों में तार्किक भी रखा है। मेकर्स ने ग्लैमर का भी भरपूर मिश्रण किया है ताकि कहानी पर असर न पड़े।

इस फिल्म में करीना कपूर, कृति सेनन, तब्बू मुख्य भूमिका में हैं। वहीं सहायक भूमिकाओं में दिलजीत दोसांझ, कपिल शर्मा से अच्छे अभिनय की उम्मीद ही की जा सकती है। क्रू में करीना कपूर सबसे अच्छी लग रही हैं। वह महत्वाकांक्षी, तेज-तर्रार, ग्लैमरस, मजाकिया और क्षमाप्रार्थी है। वैसे इस फिल्म में करीना काफी हद तक बेबो लग रही हैं। वहीं, फिल्म में तब्बू की बेहतरीन लाइनें हैं। वह केबिन क्रू में सबसे वरिष्ठ हैं और अभिनेता इसे अपने हाव-भाव, अभिनय और यहां तक कि चलने में भी कैद कर लेते हैं। अंत में, कृति सेनन बाकी दोनों पर थोड़ी भारी पड़ सकती हैं। हालाँकि, अभिनेता अपनी ऑन-पॉइंट भावनात्मक अभिव्यक्ति के साथ इसकी भरपाई करता है। किसी को यह भी लग सकता है कि दिलजीत और कृति की प्रेम कहानी को और अधिक फुटेज दिया जा सकता था, क्योंकि उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। कपिल और दिलजीत मौजूदा परिस्थितियों में अच्छे हैं लेकिन आखिरकार वे सिर्फ लीड्स का समर्थन कर रहे हैं। सहायक कलाकारों में शामिल हैं, मित्तल के रूप में राजेश शर्मा, नानू के रूप में कुलभूषण खरबंदा और विजय वालिया के रूप में सास्वता चटर्जी। अभिनेता ने वास्तव में अपनी छोटी उपस्थिति का पूरा उपयोग किया है लेकिन मित्तल उनमें से एक स्पष्ट विजेता हैं। फिल्म में कोमल का किरदार निभाने वाली पूजा भामराह भी अच्छी हैं। वह सही डोर पर प्रहार करती है।

क्रू के पास कुछ अच्छे संगीत हैं और कुछ असफल। घाघरा और चोली के पीछे क्या है को फिल्म में बखूबी रखा गया है। ये गाने भी महसूस नहीं होगी। हालाँकि, इंट्रो और सैड सॉन्ग मेरे काम नहीं आया। हालाँकि राज रंजोध इनसे बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे। दिलजीत द्वारा गाया गया नैना, जाहिर तौर पर अंतिम क्रेडिट के साथ आता है और इस फिल्म की कहानी में कुछ भी नहीं जोड़ता है। कुल मिलाकर, क्रू के पास अच्छे पार्टी गाने हैं और अब आप उन्हें पार्टियों में बजते हुए सुन सकते हैं।

प्रिय पाठकों,

इस अंक में प्रकाशित सभी अग्रलेख, कथा–लघु कथा, कविता, व्यंग्य, विचार विमर्श लेखकों एवं विचारकों की अपनी कल्पना प्रसूति हैं। त्रुटियां मानवीय स्वभाव का अंग हैं जिनकी ओर ध्यान आकृष्ट करना एक जागरूक पाठक की विशेषता होती है।

अतः आप सभी सुधी विज्ञजनों, से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि आप अपने पत्रों के माध्यम से इस अंक में प्रकाशित त्रुटियों की ओर ध्यान आकृष्ट भी समय–समय पर कराते रहें ताकि उन त्रुटियों की पुनरावृत्ति से बचा जा सके।

विवाद की स्थिति में न्यायालय, गोर खपुर का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

–व्यवस्थापक

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक पंकजधर द्विवेदी द्वारा जनप्रकाशन प्रेस, निकट रीड्स साहब का धर्मशाला से मुद्रित एवं 45 बादशाहबाग, जगन्नाथपुर, गोरखपुर से प्रकाशित। सम्पादक–पंकज धर द्विवेदी सम्पर्क सूत्र– e-mail- ghoonghatkibagawat37@gmail.com